सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 87, नई दिल्ली । शनिवार, 08 जून 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार
सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे।

03 मई के महीने ने दिल्लीवासियों किया बेहाल, एक तरफ भीषण गर्मी ने तोड़े
06 राज्य में कब बनेगा खेल प्राधिकरण
08 भारतीय जनता का ऐसा फैसला जिसे भारतीय राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा

इसी महीने मेरठ तक शुरू होगा रैपिड रेल का संचालन तैयारियां पूरी; अभी मोदीनगर तक चल रही ट्रेन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) की योजना लोकसभा चुनाव से पहले ही यात्रियों के लिए ट्रेन को मेरठ तक चलाने की थी। इसके लिए लक्ष्य से पहले काम पूरा किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

नई दिल्ली। रैपिड रेल नमो भारत इसी महीने के आखिर में मेरठ साउथ स्टेशन तक चलने लगेगी। फिलहाल प्राथमिक खंड साहिबाबाद से मोदीनगर तक चल रही ट्रेन का दायरा मेरठ तक बढ़ जाने से आठ किलोमीटर और बढ़ जाएगा। इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। ट्रायल रन पूरे किए जा चुके हैं। सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। स्टेशन भी तैयार हैं। किसी भी दिन ट्रेन के विस्तार की तारीख तय हो सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी) की योजना लोकसभा चुनाव से पहले ही यात्रियों के लिए ट्रेन को मेरठ तक चलाने की थी। इसके लिए लक्ष्य से पहले काम पूरा किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब तैयारी पूरी है। चुनाव के दौरान तेजी से काम किया गया है ।एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि मेरठ साउथ तक ट्रेन का संचालन जून के आखिरी हफ्ते तक शुरू हो जाएगा।

ऐसे चल रही तैयारी

साहिबाबाद से सराय काले खां के बीच सिविल वर्क 100 फीसदी पूरा हो चुका है। ट्रैक बिछाने का काम 50 फीसदी पूरा किया जा चुका है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच सिविल वर्क 80 फीसदी पूरा हो चुका है। बायाडक्ट रखने का काम 100 फीसदी हो चुका है।

अगले साल मार्च तक सराय काले खां तक करें सफर

मेरठ साउथ तक ट्रेनों के संचालन के बाद तीसरे खंड यानी साहिबाबाद से दिल्ली के सराय काले खां के बीच संचालन की योजना है। इस खंड में सिविल वर्क का काम शत प्रतिशत पूरा हो चुका है। ट्रैक बिछाने का काम भी 50 फीसदी से ज्यादा हो चुका है। विद्युतीकरण और स्टेशनों की फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। अगले साल मार्च तक इस रूट पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से सफर की सुविधा मिलने लगेगी। पिछले साल अक्तूबर में देश की पहली रैपिड रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। करीब 34 किलोमीटर के ट्रैक पर नमो भारत ट्रेन नियमित संचालित हो रही है। पिछले नौ महीने में इस ट्रेन से 10 लाख से अधिक लोग सफर कर चुके हैं।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathiasanjaybathia@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

बीआरओ ने दी हरी झंडी, एक-दो दिन में लेह-दिल्ली बस चलाने की तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

कुल्लू। मनाली-लेह मार्ग पर बर्फीली वादियों के बीच जल्द आम लोगों के साथ सैलानियों को एचआरटीसी की बस में सफर करने की सुविधा मिलने जा रही है। बीआरओ ने भी निगम को बस चलाने की हरी झंडी दे दी है। एचआरटीसी के केलांग डिपो ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो रविवार या सोमवार तक बस का संचालन संभव है।

बताया जा रहा है कि मंडी डिपो की दो बसें सेना के जवानों को लेकर लेह गई हैं। ऐसे में उनके लौटने के बाद केलांग से लेह तक मार्ग का पता चल सकेगा। इसके बाद निगम ट्रायल के बजाय बस को शुरू कर देगा। एचआरटीसी की यह बस सेवा करीब नौ माह बाद शुरू हो रही है। सितंबर-2023 को लेह-दिल्ली बस को बंद कर दिया था। देश के सबसे लंबे बस (1026 किमी) रूट लेह-दिल्ली में बस भले ही मात्र चार माह तक चलती है, मगर केलांग डिपो के लिए यह कमाऊ रूट है। लिहाजा केलांग डिपो ने लेह-दिल्ली रूट पर बस के संचालन को लेकर कमर कस ली है। इसको लेकर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को सीमा सड़क संगठन 70 आरसीसी के कमांडिंग आफिसर से सड़क की स्थिति को लेकर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि केलांग से लेह मार्ग बड़े वाहनों के लिए बहाल है।

सड़क दुरुस्त पाई गई तो जल्द शुरू होगी सेवा

एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यभार देख रहे निगम के अधिकारी उमेश शर्मा ने कहा कि बीआरओ के ओसी रवि शंकर से बात हुई है। उन्होंने भी बस का ट्रायल करने को कहा है। कहा कि लेह गई निगम की दो बसों के लौटने का इंतजार किया जा रहा है। अगर सड़क बसों के लिए ठीक पाई जाती है तो निगम एक-दो दिन बाद केलांग से लेह-दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर देगा।

प्रशासन ने तय किया वाहनों का समय

जिला प्रशासन ने दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही को लेकर समयसारिणी तय की है। दारचा से सरचू की तरफ सुबह 7:00 से 11:00 और सरचू से दारचा के लिए दोपहर बाद 2:00 से 5:00 बजे का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा लेह की ओर सेना की कानवाई सहित बड़े ट्रकों की आवाजाही निरंतर जारी है। इस रूट पर बस यात्री न केवल लंबे सफर का आनंद ले सकेंगे, बल्कि बर्फीले चार दर्रां का भी लुत्फ उठा पाएंगे। बता दें कि चार दर्रों के बीच से होकर गुजरने वाली लेह-दिल्ली बस सेवा सितंबर के बाद से बंद है।

आरसी को लेकर दिल्ली परिवहन विभाग सख्त डीलरों को देना होगा रिपोर्ट, मंत्री ने दिए निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

वाहन डीलरों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) नहीं सौंपने की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

नईदिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने सभी जिला कार्यालयों (आरटीओ) को अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले वाहन डीलरों से वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने पर पाक्षिक आधार पर रिपोर्ट मांगने का निर्देश दिया है। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया है कि वाहन विक्रेता वाहनों की खरीद के समय खरीदारों को पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं सौंप रहे हैं।

दिल्ली सरकार ने 2021 में यह सुविधा शुरू की थी, जिसमें वाहन खरीदार सीधे अपने डीलर से अपने वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) प्राप्त कर सकेंगे। कई ऐसे डीलर भी हैं जिनके पास स्व- पंजीकरण की सुविधा है। लेकिन, परिवहन विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि वाहन डीलर मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं।

परिवहन विभाग द्वारा 6 जून को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि स्व-पंजीकरण सुविधा वाले वाहन डीलर वाहन की डिलीवरी के समय पंजीकृत वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं सौंप रहे हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में 30 दिनों से अधिक देरी की जा रही है। विभाग ने अपने आदेश में सभी जिला परिवहन कार्यालयों (डीटीओ) को निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक डीलर से वाहन की डिलीवरी की तारीख और प्रत्येक वाहन के लिए आरसी की डिलीवरी की तारीख पर पाक्षिक रिपोर्ट लें और इसे तीन दिनों के भीतर संचालन शाखा को भेजें।

आदेश में इस संबंध में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने यह आदेश दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निर्देश के बाद जारी किया है। गहलोत ने बताया कि मुझे वाहन डीलरों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी करने की कई शिकायतें मिल रही थीं। उसके बाद मैंने परिवहन विभाग को इस संबंध में आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

बड़ा सवाल: आखिर क्यों...दुर्घटना के बाद ही क्यों जागता है परिवहन विभाग? 12 घंटे में 205 वाहनों के चालान काटे

परिवहन विशेष न्यूज

पतलोट में हुई दुर्घटना के दूसरे दिन परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर 12 घंटे में ही 205 वाहनों के चालान काट दिए। तीन वाहनों की फिटनेस निरस्त कर दी और तीन वाहनों के परमिट निरस्त करने की संस्तुति भी की।

नैनीताल। पर्वतीय और मैदानी रूट पर जब जब सड़क हादसे होते हैं तो उसके तुरंत बाद परिवहन विभाग की नींद खुलती है और वह ताबड़तोड़ चैकिंग अभियान चलाकर वाहनों के चालान करने में जुट जाता है। विभाग की यह कार्रवाई दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं जो कि हादसों के एक दो दिन तक चलती है और उसके बाद फिर से महीनों तक चैकिंग जैसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पतलोट में हुई दुर्घटना के दूसरे दिन परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर 12 घंटे में ही 205 वाहनों के चालान काट दिए। तीन वाहनों की फिटनेस निरस्त कर दी और तीन वाहनों के परमिट निरस्त करने की संस्तुति भी की।

पतलोट हादसे के बाद अधिकारी हरकत में आए और बृहस्पतिवार को चालान करने के लिए पर्वतीय रूट पर पांच अलग अलग टीमें उतार दी गई। जैसे ही अधिकारी चैकिंग करने लगे तो टैक्सी चालकों का तंत्र सक्रिय हुआ और सड़कों में एक छोर से दूसरे छोर तक चैकिंग की बात एक दूसरे तक पहुंचा दी गई और देखते ही देखते पर्वतीय रूट में अधिकांश ओवरलोड चलने वाले वाहन सड़कों से गायब हो गए। इसके बाद भी परिवहन विभाग की टीम ने 205 वाहनों के चालान किए। जिसमें 13 यात्री वाहनों का ओवरलोड में चालान किया गया। इसके अतिरिक्त छह बिना फिटनेस, पांच बिना परमिट, 13 बिना कर, छह बिना डीएल के चालान किए गए। पर्वतीय क्षेत्रों में ओवरलोडिंग के लिए प्रयोग किए जाने में अनधिकृत कैरियर के 26 वाहनों के चालान किए गए। तीन वाहनों की फिटनेस मार्ग में निरस्त भी की गई है। इसके अतिरिक्त तीन वाहनों के परमिट के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

हल्द्वानी में भी चला अभियान

बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग ने हल्द्वानी में भी अभियान चलाया। इस दौरान ओवर स्पीड दौड़ रहे 17 वाहनों के भी चालान किए गए। उधर 58 बिना हेल्मेट के वाहन चलाने और पीछे बैठे यात्री के पास हेल्मेट नहीं होने पर चालान किए गए।

ये वाहन पर्वतीय रूट पर हैं पास छोटी बसें 28 से 32 सीट पर

टैक्सी - पर्वतीय रूट में सात से 10 सीटर टैक्सी चलती है।

मैक्सी- पर्वतीय रूट पर चलने वाली मैक्सी आठ से 13 सीट में पास हैं।

सीट से अधिक सवारी भरने में इतने का होता है चालान

परिवहन विभाग का जुर्माना 200 रुपये प्रति सीट

आरटीए का जुर्माना 1000 रुपये प्रति सीट

रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगता है।

बार-बार ओवरलोडिंग करने पर परमिट और चालक का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।

ओवरलोड की यहां करें शिकायत

एआरटीओ प्रवर्तन - रश्मि भट्ट 9027115122

टीटीओ प्रवर्तन - प्रमोद चौधरी 9997243814

गाड़ी की छत पर सामान रखने के लिए कैरियर लगाया तो होगा 2500 का चालान

परिवहन विभाग सवारी वाहनों की छत में सामान रखने के लिए कैरियर लगाने पर भी कार्रवाई करेगा। आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि सभी यूनियनों को पत्र भेजकर गुड्स कैरियर हटाने के लिए कहा है। कहा कि सोमवार से इस पर कार्रवाई की जाएगी। गुड्स कैरियर जब्त किए जाएंगे। साथ ही 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आरटीओ की जांच में आया सामने, नहीं थे पैरापिट

आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बृहस्पतिवार को पतलोट में वाहन गिरने वाले स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर वाहन खाई में गिरा वहां पर पैरापिट नहीं थे। उनकी जगह कोलतार के खाली ड्रमों में मिट्टी भरकर रखा गया था। जो गाड़ी टकराने के बाद नीचे चला गया। कहा कि पैरापिट होते तो वाहन खाई में नहीं जाता।

सड़क दुर्घटना में घायलों को एक घंटे में मिल जाना चाहिए इलाज

सड़क दुर्घटना में घायलों को एक घंटे के अंदर इलाज मिल जाना चाहिए। इसे गोल्डन घंटा कहा जाता है लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसे हादसों के दौरान घायलों को तुरंत इलाज नहीं मिल पाता है। इलाज में देरी ही कई बार घायलों के मौत का कारण बनती है।

रावी पुल के डिजाइन में उलझी एक्सप्रेस-वे की रफ्तार, अब एक साल और इंतजार

पंजाब के बलसुआ से हीरानगर तक काम पैकेज 14 के अधीन हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पैकेज में रावी के पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कतों के चलते परियोजना को पूरा करने का समय बढ़ने वाला है।

जम्मू। उत्तर भारत में केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे की रफ्तार रावी दरिया पर बनाए जा रहे पुल के डिजाइन में उलझ गई है। सितंबर 2024 की तय समय सीमा में अब यह परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इस सड़क पर सफर करने के लिए करीब एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेस-वे के तैयार होने के बाद दिल्ली से कटड़ा का सफर छह से सात घंटे में पूरा किया जा सकेगा।

670 किलोमीटर लंबे दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे का काम 39 हजार करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। पंजाब के बलसुआ से हीरानगर तक काम पैकेज 14 के अधीन हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पैकेज में रावी के पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कतों के चलते परियोजना को पूरा करने का समय बढ़ने वाला है। हाईवे प्राधिकरण हालांकि इस काम को मार्च, 2025 तक पूरा करने के प्रयास में जुटा है।

उधर, पैकेज 15 में हीरानगर से जख तक काम होगा, जिसमें रिंग रोड जम्मू का जंक्शन भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बसंतर पर बनने वाले पुल का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि विजयपुर में बनने वाले 1.35 किलोमीटर लंबे और इस एक्सप्रेस-वे को ऊंचाई देने वाले ढांचे के निर्माण में अधिक समय लगना तय है। पैकेज 16 में जख से कुंजवानी तक काम किया जा रहा है। इसमें चौथे तवी पुल के साथ-साथ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी शामिल है। फिलहाल इस पैकेज का काम 45 फीसदी तक ही हो पाया है।

इस कारण भी हो रही देरी : सतवारी में 38 ढांचों को हटाए जाने का काम बाकी रहने से भी परियोजना का काम पिछड़ रहा है। ऐसे में यह पैकेज भी सितंबर 2024 तक पूरा नहीं होने जा रहा। पैकेज 17 के तहत कुंजवानी से सिद्दड़ा और दोमेल से कटड़ा तक काम किया जाना है।

सूत्रों की मानें तो जून 2023 में अवार्ड हुए इस काम के तहत रेलवे की टनल और जमीन के बीच में आने से काम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्राधिकरण ताराकोट की जगह इस पैकेज को इंटर मॉडल स्टेशन कटड़ा तक ही पूरा करने पर विचार कर रहा है। पैकेज 18 में सिद्दड़ा से बन के बीच काम किया जाना है, जिसमें अबतक दो प्रतिशत ही काम पूरा हो सका है। ऐसे में साफ है कि परियोजना को लेकर तय किए गए समय में इसे किसी भी सूरत में पूरा नहीं किया जा सकेगा। उधर, प्रशासन और केंद्र सरकार भी परियोजना पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस परियोजना को जल्द पूरा करने को लेकर भी नजर रखी जा रही है।

आजाद हिंदुस्तान की पहली महिला पायलट के बारे में कितना जानते हैं आप?

हमारे देश में कई महिलाओं के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन हम आपको इतिहास रचने वाली पायलट उषा सुंदरम की इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताएंगे।

आजाद हिन्दुस्तान के पीछे ऐसी कई महिलाओं का हाथ है, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए पूर्ण योगदान दिया है। इतिहास के पन्नों में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जिन्हें पढ़ जाना चाहिए। हिन्दुस्तान में बसे हर राज्य और क्षेत्र की अपनी अलग कहानी और संघर्ष हैं यहां तक की उड़ान के क्षेत्र में भी। क्योंकि एक वक्त था जब महिलाएं अपने घर से बाहर तक नहीं मिलती थीं और महिलाओं की क्षमता को पायलट के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचाते थे।

लेकिन आज विमान क्षेत्र में पायलट महिला की भरमार है। हालांकि, 1947 में डोमेस्टिक एयरलाइन उड़ाने वाली प्रेम माथुर, पहली भारतीय कमर्शियल पायलट बनी थीं। वहीं, दुर्बा बनर्जी, 1956 में इंडियन एयरलाइन्स की पहली महिला पायलट बनी थीं। लेकिन आज हम आपको आजाद हिंदुस्तान की पहली उषा सुंदरम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं।

20 साल की उम्र में उड़ना सीखा-

Usha sundaram ( )

उषा सुंदरम स्वतंत्र भारत की पहली महिला पायलट थीं। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने कम उम्र से कई महत्वपूर्ण घटनाओं और मिशनों को सुगम बनाया और अपने सपनों की तरफ उड़ान भरना शुरू की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एविएशन में अपना करियर बनाने की सोची। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र में उषा सुंदरम ने उड़ना भरना सीखा था। फिर 22 साल की उम्र में उषा सुंदरम ने पिस्टन-इंजन के साथ इंग्लैंड से भारत की उड़ान में सबसे तेज उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था।

23 घंटे की उड़ान भरकर बनाया था रिकॉर्ड-

उषा सुंदरम 1948 में स्वतंत्र भारत के बाद पहली महिला पायलट थीं। लेकिन सरला ठकराल 1936 में लाहौर फ्लाइंग क्लब के लिए उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला थीं। बता दें कि उषा ने आखिरी बार 1951 में एक उड़ान की कमान संभाली थी। इस दौरान उन्होंने अपने पायलट-पति के साथ लंदन से चेन्नई तक 23 घंटे की उड़ान भरकर एक रिकॉर्ड बनाया था। आज भी पिस्टन इंजन वाले विमान के लिए यह रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके बाद वह द ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की सह-संस्थापक बनी थीं।

1952 में हुई थीं रिटायर-

देश के आजाद होने के बाद उषा ने अपने जलवे कई सालों तक अपने जलवे बिखेरे और पहली महिला पायलट होने का खिताब अपने नाम किया। लेकिन कहा जाता है कि उषा ने अपने रियाटरमेंट से पहले अपने साहस लोगों की जान बचाने का भी काम किया था। (संगीता गौड़ की इंस्पायरिंग स्टोरी) इतिहास के अनुसार भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम किया था और सुरक्षित उन्हें अपने घर वापस पहुंचाया था। लेकिन इसके बाद 1952 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और इसके बाद इन्होंने विमान के क्षेत्र को अलविदा कह दिया था।

भारत की पहली महिला पायलट जो साड़ी पहन उड़ाती थीं प्लेन, जानें सरला ठकराल से जुड़ी 7 रोचक बातें

सरला ठकराल ये वो नाम है जिसने महिलाओं को आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ना सिखाया। वह विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने साड़ी पहनकर कॉकपिट में प्रवेश किया था। आइए जानते हैं पायलट सरला ठकराल की जिंदगी से जुड़े सात रोचक तथ्य।

महिलाओं को थोड़ी आजादी मिल जाए तो वह आसमान की ऊंचाईयों को नाप सकती हैं। ऐसा ही कुछ सरला ठकराल ने 1936 में किया था। 21 साल की उम्र में सरला ठकराल ने साड़ी पहन कर एयरक्राफ्ट से साथ उड़ान भरी थी।

ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला पायलट (India's First Women Pilot) थीं। आइए जानते हैं सरला ठकराल के बारे में रोचक तथ्य। दिल्ली में जन्मी सरला बेहद महत्वाकांक्षी थीं। 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। सरला के पति के घर में सभी पायलट थे। सरला को 21 साल की उम्र में एविएशन पायलट का लाइसेंस मिला था। उन्होंने 1000 घंटे से अधिक की उड़ान भरने के बाद अपना 'ए' लाइसेंस प्राप्त किया था।

जब सरला ने अपनी पहली उड़ान भरी, तब वह न सिर्फ शादीशुदा थीं। बल्कि चार साल के बेटी की मां भी थीं।

ऐसे समय में जब विमानन केवल पुरुषों के लिए था। उस समय पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सरला ने जिप्सी मॉथ के कॉकपिट में साड़ी पहन कर प्रवेश किया था।

1939 में जोधपुर में प्रशिक्षण के दौरान उनके पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह 24 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं। तब उन्होंने कमर्शियल पायलट बनने के अपने सपने को पीछे छोड़ दिया था।

पति की मौत के बाद सरला ने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स से ललित कला में डिप्लोमा लिया। भारत बंटवारे के बाद वह अपनी दो बेटियों के साथ दिल्ली आ गईं।

इसके बाद वह एक उद्यमी बन गईं। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आभूषण निर्माण, साड़ी डिजाइनिंग, पेंटिंग और डिजाइनिंग का कार्य किया। इनके ग्राहकों की लिस्ट में विजयलक्ष्मी पंडित भी शामिल थीं।

एक हादसे ने बदली जिंदगी

साल 1939 में एक प्लेन हादसा हुआ। इस प्लेन क्रैश में सरला के पति की मौत हो गई थी। इस वक्त वह मात्र 24 साल की थीं। इसके कुछ समय बाद, उन्होंने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, हालांकि तभी विश्व युद्ध-2 शुरू हो गया था, जिस वजह से सारी सिविल ट्रेनिंग निलंबित कर दी गई थी।

इसके बाद बेटियों की परवरिश के लिए उन्होंने सपना छोड़ दिया। उन्होंने लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया था। वह पार्टीशन के बाद दिल्ली आयी थीं।

सिजेरियन डिलीवरी के बाद वजन बढ़ने की ना करें चिंता

लाइफस्टाइल में शामिल कर लें 3 व्यायाम, तेजी से घटेगा वजन

C-Section Recovery Exercises: सिजेरियन डिलीवरी के बाद अक्सर डॉक्टर मां को ब्रेस्ट फीड कराने की सलाह देते हैं, जिससे बच्चे की तो सेहत अच्छी रहती ही है, मां का वजन भी कंट्रोल में रहता है. लेकिन, कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइज हैं, जिसकी मदद से मांएं आसानी से अपने वजन को कम कर सकती हैं.

सिजेरियन डिलीवरी के बाद कुछ खास एक्सरसाइज फैट कम करने में मदद कर सकता है. Image : Canvaसिजेरियन डिलीवरी के बाद कुछ खास एक्सरसाइज फैट कम करने में मदद कर सकता है.

सिजेरियन डिलीवरी के बाद अक्सर डॉक्टर मां को ब्रेस्ट फीड कराने की सलाह देते हैं, जिससे बच्चे की तो सेहत अच्छी रहती ही है, मां का वजन भी कंट्रोल में रहता है. लेकिन, कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइज हैं, जिसकी मदद से मांएं आसानी से अपने वजन को कम कर सकती हैं.

C-Section Rehabilitation Exercises: सिजेरियन डिलीवरी एक ऐसी सर्जरी है, जिसमें बच्चे को जल्दी और सुरक्षित रूप से जन्म देने के लिए ऑपरेशन किया जाता है. सिजेरियन डिलीवरी के बाद रिकवरी का समय नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में थोड़ा लंबा होता है. इस वजह से उनका वजन तेजी से बढ़ने लगता है. बढ़ते वजन को रोकने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद कुछ सिंपल व्यायामों की मदद ले सकती हैं.

क्यों बढ़ता है वजन

हेल्थलाइन के मुताबिक, दरअसल सिजेरियन डिलीवरी के बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की मांसपेशियां, मसलन रीढ़, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों, पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों कमजोर हो जाती हैं. सिजेरियन डिलीवरी के बाद, इन क्षेत्रों को सक्रिय और मजबूत करना जरूरी होता है, जिससे रिकवरी फास्ट हो. ऐसे में अगर आप सी-सेक्शन के बाद डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ खास एक्सरसाइज करें तो आप अपने बढ़ते फैट को कम कर सकती हैं और फिट दिख सकती हैं.

मोटापा कंट्रोल करेंगी ये ड्रिंक

मोटापा कंट्रोल करेंगी ये ड्रिंकआगे देखें...

सिजेरियन डिलीवरी के बाद करें ये 3 व्यायाम

बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज

कोर मसल्स की मजबूती के लिए आप बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें. इसके लिए आप बेड पर लेट जाएं. अपने हाथों बेली पर रखें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें. अब इस तरह गहरी सांस लें कि आपके बेली पर रखा हाथ उठने लगे. अब 3 सेंकेंड तक होल्ड करें. फिर मुंह से सांस छोड़ें, जिससे पेट का बेली बटन अंदर की तरफ जाए. ऐसा 10 बार करें.

वॉल सिट एक्सरसाइज

यह एक फुल बॉडी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिसमें लोअर बैक से लेकर, कोर, पेल्विक फ्लोर आदि भी मजबत बनता है. इसे करने के लिए दीवार से 1 से 2 फीट की दूरी पर खड़े हो जाएं. अब धीरे से दीवार पर सटें और बैठने के पोजीशन में आ जाएं. अब गहरी सांस लें और निकालें. अपने पेट को अंदर की तरफ खींचन की कोशिश करें. प्रयास करें कि 1 मिनट तक इसी पोजीशन में होल्ड करें.

लेग स्लाइड

सर्जरी के 6 से 8 सप्ताह के बाद आप इस व्यायाम को कर सकती हैं. बॉडी कोर मसल्स और पेट के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए अब आप मैट पर लेट जाएं. अब पैर के नीचे कोई टॉवल रखें. अब घुटनों को मोड़ते हुए अपने फुट को जमीन पर रखें. अब गहरी सांस लें. अब पैर को धीरे धीरे सीधा करें और जमीन से बिना सटाए वापिस पहले पोजीशन में आ जाएं.इसी तरह दोनों पैरों से ये व्यायाम करें. 10 बार इसे करें.

धीरे-धीरे अभ्यास करते-करते आप पाएंगी कि आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं और फैट गायब हो रही है. हालांकि, अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन व्यायामों को अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना बेहतर रहेगा.

बच्चे ही नहीं, समर वेकेशन में मांएं भी जरूर सीख लें 5 जरूरी काम, बोरियत होगी दूर, बढ़ेगा आत्मविश्वास

गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और बच चे घर पर रह कर ही पढ़ाई और मौज-मस ती कर रहे हैं. ऐसे में मांओं और हाउस फाइफ के लिए अपने लिए वक त निकालना आसान हो गया है. यहां हम बता रहे हैं कि आप इस समर वेकेशन में बच चों के साथ-साथ खुद भी क या नया सीख सकती हैं.

अक्सर महिलाएं परिवार और बच्चों को संभालने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें अपने पसंद और नापसंद का ख्याल ही नहीं होता. परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वे अपनी हॉबीज को भूल जाती हैं, जो उनके लाइफ में खुशहाली लाने की बड़ी वजह बन सकता है. ऐसे में समर वेकेशन केवल बच्चों के लिए ही नहीं, मांओं के लिए भी एक मौका लेकर आता है, जब आप जरूरी चीजों को सीखने के लिए वक्त निकाल सकती हैं. ये एक्टिविटीज आपके हुनर को बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कि महिलाएं समर वेकेशन में किन-किन चीजों को सीख सकती हैं.

समर वेकेशन में महिलाएं जरूर सीखें ये काम

स्विमिंग

अक्सर महिलाएं बचपन से ही व्यस्तताओं की वजह से तैरना नहीं सीख पाती हैं. ऐसे में अपना समय आने का इंतजार करने से बेहतर है कि आप इस समर वेकेशन में स्विमिंग क्लास जॉइन करें और इस पेंडिंग पड़े काम को पूरा कर लें.

गार्डनिंग

अगर आपको गार्डेनिंग का शौक है तो आप आसपास चल रहे गार्डेनिंग क्लास को ज्वाइन करें. आप ऑनलाइन क्लास की मदद से भी यह काम पूरा कर सकती हैं. आप चाहें तो बोनसाई, किचन प्लांटिंग, टैरिस प्लांटिंग आदि में एक्सपर्ट भी बन सकती हैं.

डांस

अगर आप पार्टी आदि में जाने में डांस नहीं कर पातीं और आपको इस वजह से शादी या किसी स्पेशल ओकेशन में कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप समर वेकेशन में डांस क्लास ज्वाइन करें. आप इसके लिए बॉलीवुड डांस, कॉन्टेम्परी डांस आदि के शॉर्ट कोर्स को ज्वाइन करें.

योग करें

अगर आप अब तक केवल योगा क्लास करने की सोच ही रही हैं तो अब समय आ गया है कि आप झट से योगा क्लास ज्वाइन करें. ये वो वक्त है जब आप अपने लिए सुबह या शाम का वक्त निकाल सकते हैं.

क्या इस्तीफा देंगे केजरीवाल? दिल्ली के सियासी संकट से जुड़े दो संकेत और एक बड़े दावे से समझें A TO Z

केंद्र में ना तो आइएनडीआइ गठबंधन की सरकार बनी और ना ही कोर्ट से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आबकारी मामले में कोई राहत मिली है। जब दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लगी तो अब सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल के सामने दिल्ली में अपनी सरकार बचाने को लेकर है। एलजी सक्सेना पहले ही कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्र में न आइएनडीआइ गठबंधन की सरकार बनी और न अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। दोनों तरफ से निराशा मिलने के बाद अब केजरीवाल के सामने दिल्ली में अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। इस बीच दिल्ली की सियासत पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक ओर जहां एलजी पहले ही कह चुके हैं कि वह जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, वहीं अदालत से भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। ऐसे में वह कब तक जेल से बाहर आएंगे कोई निश्चित नहीं है।

इस बीच दिल्ली में नया सियासी भूचाल आ सकता है, जिसे लेकर दो संकेत और एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। हम जिन दो संकेतों की बात कर रहे हैं उसमें से पहला है दिल्ली के सीएम को जमानत न मिलना।

दूसरा संकेत है गुरुवार को सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल की अध्यक्षता में पहली बार कोई बैठक हुई। इस बैठक से भाजपा के उस दावे को बल मिलता है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर पत्नी सुनीता को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं।

क्या हैं वर्तमान हालात

गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्पष्ट कर चुके हैं कि वह जेल से दिल्ली सरकार नहीं चलने देंगे। दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर वह सख्त कदम उठाने के भी संकेत दे चुके हैं। इससे आप सरकार के भविष्य को लेकर कयास लगने लगे हैं।

ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। वहीं, भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है।

दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है-भाजपा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व अन्य नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से दिल्ली का विकास बाधित हो रहा है। महापौर का चुनाव नहीं हो सका है। दिल्लीवासियों के हित में उन्हें अविलंब त्यागपत्र देकर किसी और विधायक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

क्या कहते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव

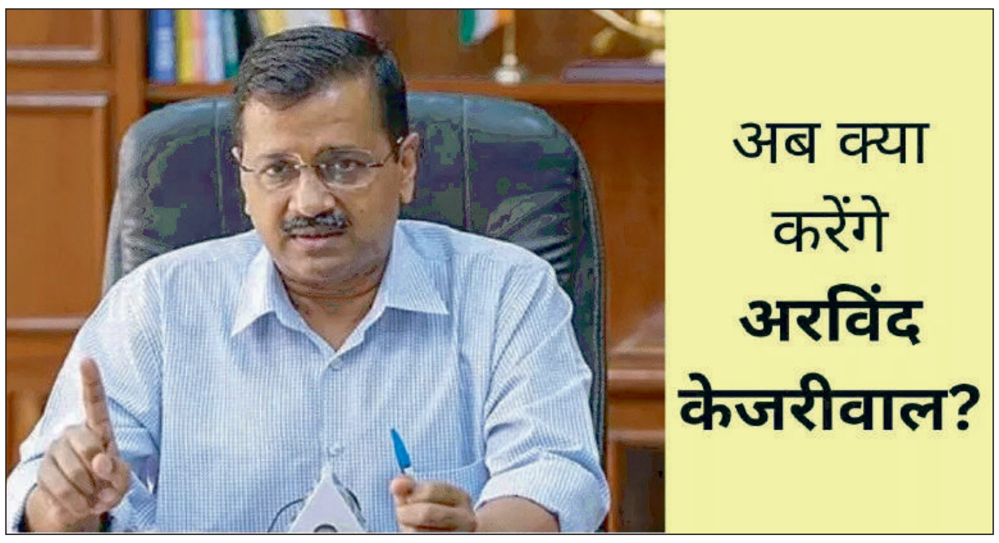

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल का मानना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने से सामान्य प्रशासनिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, परंतु बड़े निर्णय नहीं हो सकते।

यदि लंबे समय तक वह जेल में रहेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास व अन्य कार्य बाधित होंगे। महत्वपूर्ण फाइलें मुख्यमंत्री की अनुशंसा से उपराज्यपाल के द्वारा पास की जाती है।

राजनीतिक जानकारों की क्या है राय

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केजरीवाल (Kejriwal News) को यह उम्मीद रही होगी कि केंद्र में आइएनडीआइ गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन्हें राहत मिल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। इस कारण आने वाले दिनों में उनकी सरकार की परेशानी बढ़ेगी।

सरकार बचाने के लिए सौंपनी होगी किसी और को कुर्सी

आप सरकार को बचाने के लिए उन्हें त्यागपत्र देकर किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपनी होगी। उनके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे या फिर अपने किसी विधायक को।

भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इसके लिए वह पार्टी में सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसे लेकर पार्टी में असंतोष भी है।

पति की अनुपस्थिति में सुनीता आई फ्रंटफुट पर

पति के जेल जाने के बाद से सुनीता केजरीवाल राजनीति में सक्रिय हुई हैं। 31 मार्च को आइएनडीआइए की रामलीला मैदान में हुई रैली में उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई थी।

पति की अनुपस्थिति में वह लोकसभा चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल रही थीं। बृहस्पतिवार को सीएम की अनुपस्थिति में उनके आवास पर विधायकों की बैठक हुई। ऐसे में, भाजपा के आरोप को बल मिलता है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने लगाए ये आरोप

दिल्ली भाजपा (Delhi BJP) के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) का कहना है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार का विरोध कर सत्ता तक पहुंचने वाले केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में वह जेल में हैं।

अपने बचाव के लिए वह उन लोगों की शरण में चले गए हैं जिन्हें कभी भ्रष्टाचारी और परिवारवाद बढ़ाने का आरोप लगाकर उनका विरोध करते थे। अब न उन्हें भ्रष्टाचार से परहेज है और न परिवारवाद से।

यही कारण है कि भ्रष्टाचार में जेल जाने के बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली के हित में उन्हें अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।

कुलदीप सिंह सेंगर को दी दस साल की जेल को निलंबित करने से हाईकोर्ट का इनकार, दुष्कर्म आरोप में कट रहा सजा

यूपी के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दल साल की सजा सुनाई गई थी। जिसको लेकर उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी कि उसकी सजा को निलंबित किया जाए। जिसे कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है। बता दें दुष्कर्म के मामले में सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहा है।

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई दस साल की जेल की सजा को निलंबित करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इसके साथ ही दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान मामले में सजा को निलंबित करने की मांग वाली कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि यह अदालत इस स्तर पर सजा को निलंबित करने की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है।

दिल्ली के 44 अस्पतालों में पाई गईं कमियां, एसीबी ने सतर्कता विभाग को भेजी रिपोर्ट; बहुतों का खत्म हुआ लाइसेंस

परिवहन विशेष न्यूज

25 मई को विवेक विहार स्थित अस्पताल में भीषण आग लगने से सात शिशुओं की मौत हो जाने के बाद एसीबी की टीम ने एक सप्ताह में दिल्ली के 62 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। संयुक्त आयुक्त एसीबी मधुर वर्मा का कहना है कि आपरेशन के पहले चरण में अभी केवल 62 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों का निरीक्षण किया गया जिनमें चार अस्पताल बिना लाइसेंस के चलते पाए गए।

नई दिल्ली। विवेक विहार में नियम कानून को ताक पर रखकर चल रहे बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल में आग लगने से सात शिशुओं को मौत के बाद उप राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दिल्ली में चल रहे 62 निजी अस्पतालों की गहन जांच करने पर 44 अस्पतालों में कमियां पाई गई।

इन अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, पंजीकरण और नियामक प्रबंधन की जांच में चार निजी अस्पताल बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलते हुए पाए गए और 40 अन्य में भी कई कमियां पाई गई हैं।

25 मई को विवेक विहार में लगी थी आग

25 मई को विवेक विहार स्थित अस्पताल में भीषण आग लगने से सात शिशुओं की मौत हो जाने के बाद एसीबी की टीम ने एक सप्ताह में दिल्ली के 62 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया।

संयुक्त आयुक्त एसीबी मधुर वर्मा का कहना है कि आपरेशन के पहले चरण में अभी केवल 62 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों का निरीक्षण किया गया, जिनमें चार अस्पताल बिना लाइसेंस के चलते पाए गए।

इन चार अस्पतालों में एक कृष्णा नगर, एक कोंडली, एक राजौरी गार्डन व एक देवली में स्थित है। ये अस्पताल संबंधित प्राधिकारी से कोई लाइसेंस दिखाने या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने में विफल रहे।

जिन 40 अन्य अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं व कई विसंगतियों के साथ चलती पाई गईं। उनमें से कुछ स्वीकृत क्षमता के मुकाबले अधिक बिस्तरों के साथ चल रहे हैं, कुछ बिना फायर एनओसी, उचित अग्नि उपायों, पुराने अग्निशामक यंत्रों या समाप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के चल रहे हैं।

सतर्कता विभाग को भेजी गई रिपोर्ट

एसीबी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने पहले चरण के निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट बनाई है जिसे सतर्कता विभाग को भेज दी जाएगी। सतर्कता विभाग, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहेगा। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

एसीबी का कहना है कि जल्द ही निरीक्षण का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली में 1000 से अधिक निजी अस्पताल और नर्सिंग होम हैं।

31 मार्च को खत्म हुआ लाइसेंस फिर भी...

बेबी केयर न्यू बोर्न अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची व एक सीनियर डाक्टर को दिल्ली पुलिस ने आग की घटना के अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि अस्पताल में अग्नि-सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन पाया गया था। साथ ही अस्पताल में स्वीकृत क्षमता से अधिक बच्चों को रखा जाता था।

अस्पताल का लाइसेंस भी 31 मार्च को समाप्त हो गया था। एसीबी अधिकारियों के अनुसार जांच टीमें अस्पताल और नर्सिंग होम चलाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण प्रमाणपत्रों की जांच कर रही हैं।

वे उचित पंजीकरण प्रमाणपत्र, लाइसेंस और सुरक्षा मानदंडों के बिना, अपने क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं को संचालित करने की अनुमति देने में सरकारी अधिकारियों की कथित संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं।

वेलकम इलाके में एक साथ दो शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप, मौत की बताई जा रही है ये वजह

वेलकम इलाके में संदिग्ध हालात में दो दोस्तों की मौत का मामला सामने आया है। मृतको की पहचान दानिश व फिरोज के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है दोनों के शव नीले पड़ गए हैं। आशंका जताई है कि जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई है।दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पूर्वी दिल्ली। वेलकम इलाके में संदिग्ध हालात में दो दोस्तों की मौत का मामला सामने आया है। मृतको की पहचान दानिश व फिरोज़ के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है दोनों के शव नीले पड़ गए हैं। आशंका जताई है कि जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई है।दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस (Delhi Police) ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मई के महीने ने दिल्लीवासियों किया बेहाल, एक तरफ भीषण गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड; जल संकट ने लोगों की बढ़ाई परेशानी

परिवहन विशेष न्यूज

मई का महीना दिल्लीवासियों के लिए कहर बनकर बरपा। उच्चतम तापमान के कारण भीषण गर्मी देखी गई। पेयजल संकट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। गैर सरकारी संस्था क्लाईमेट ट्रेंडस द्वारा किए गए एक विश्लेषण में ये बात सामने आई। नई दिल्ली जालंधर और लरकाना वर्तमान में अतीत की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म रहा।

नई दिल्ली। देश के उत्तरी और मध्य भागों में 26 मई से 29 मई के बीच अभूतपूर्व लू का प्रकोप देखने को मिला। नई दिल्ली में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के 37 से अधिक शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। लू से संबंधित बीमारियों की चेतावनी जारी की गई और कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर हैं।

दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 45.2 से 49.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज

गैर सरकारी संस्था क्लाइमेट ट्रेंडस का विश्लेषण बताता है कि देश में मई में पड़ी लू जैसी घटना पहले देखी गई सबसे गर्म लू से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म थीं। शोधकर्ता भारत में मई महीने की लू को एक अनोखी घटना के रूप में देखते हैं, जिसकी विशेषताओं को ज्यादातर मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

हालांकि दिल्ली के मुंगेशपुर में 53.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने की खबरें भी आई थीं, लेकिन बाद में पता चला कि खराब सेंसर के कारण गलत आंकड़ा था। फिर भी, भारत और दक्षिणी पाकिस्तान में चली लू ने रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान 45.2 से 49.1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए 200 टीमों की तैनाती

दिल्ली में पानी की कमी को देखते हुए जल मंत्री आतिशी ने चेतावनी दे दी कि पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति भी कम कर दी गई। आतिशी का कहना था कि नल से गाड़ियां धोने और टंकियों को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए 200 टीमों को तैनात किया जाएगा।

तापमान के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिणी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तापमान विसंगतियों में पांच डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। वर्षा का डेटा उस क्षेत्र के बड़े हिस्से में वर्षा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। वहीं हवा की गति का डेटा धीमी से मध्यम हवाओं को दर्शाता है।

> “
> दिल्ली में पानी की कमी को देखते हुए जल मंत्री आतिशी ने चेतावनी दे दी कि पानी की बर्बादी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति भी कम कर दी गई। आतिशी का कहना था कि नल से गाड़ियां धोने और टंकियों को ओवरफ्लो होने से रोकने के लिए 200 टीमों को तैनात किया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पैनल (आइपीसीसी) की छठी आंकलन रिपोर्ट देश में लू और जलवायु परिवर्तन के बीच स्पष्ट संबंध को इंगित करती है। जलवायु परिवर्तन विभिन्न तरीकों से देश में लू की घटनाओं में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

जलवायु परिवर्तन से भूमि की स्थिति में परिवर्तन होने की आशंका है, जो क्षेत्रों में तापमान और वर्षा को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक तापमान और शहरीकरण लू के दौरान शहरों और उनके आसपास गर्मी को बढ़ा सकते हैं, जिसका रात के तापमान पर दिन के तापमान की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है।

वर्षा में नहीं दिखा कोई खास बदलाव

विश्लेषण बताता है कि मई में भारत में पड़ी तीव्र गर्मी जैसी घटनाएं वर्तमान (2001-2023) की तुलना में अतीत (1979-2001) में किस प्रकार भिन्न थीं। विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान जलवायु में अतीत की तुलना में इस क्षेत्र में समान घटनाएं कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म तापमान उत्पन्न करती हैं। वहीं वर्षा में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला है।

यह भी पाया गया कि अतीत में ऐसी घटनाएं आमतौर पर नवंबर और दिसंबर में हुआ करती थीं, जबकि वर्तमान जलवायु में ये ज्यादातर फरवरी और मई में हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों में बदलावों से पता चलता है कि नई दिल्ली, जालंधर और लरकाना वर्तमान में अतीत की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हैं।

यह निष्कर्ष मौसम विभाग द्वारा 53.2 डिग्री की गलत रीडिंग हटाने के बाद समायोजित रीडिंग के अनुरूप है। विश्लेषण में ये भी पाया गया कि पेसिफिक डेकेडल ओसिलेशन (पीडीओ) जैसी प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के स्रोतों ने इस घटना को प्रभावित किया हो सकता है। इसका मतलब है कि हम जो बदलाव देख रहे हैं, वे ज्यादातर मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकते हैं।

संपत नेहरा नाम पर सूझी बदमाशी, प्रॉपर्टी डीलर को मारने आए बदमाशों से नहीं चली पिस्टल, होने लगा शोर, और फिर'

परिवहन विशेष न्यूज

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 4 जून को वह अपने पीएसओ के साथ कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने एक युवक को कार्यालय की ओर आते देखा। उसके हाथ में पिस्टल था। जिससे उसने उन पर दो बार गोली चलाने का प्रयास किया। लेकिन उसके पिस्टल गोली नहीं चली। यह देखकर कारोबारी ने पीएसओ को आवाज लगाई।

बाहरी दिल्ली। नरेला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक प्रापर्टी डीलर से गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर बदमाशों ने फोन कर पहले रंगदारी मांगी। फिर कोई जवाब न मिलने पर प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाने की कोशिश भी की, लेकिन पिस्टल में खराबी आने से गोली नहीं चल पाई।

कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों का पता लगा रही है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक कारोबारी अपने परिवार के साथ नरेला में रहते हैं। नरेला बवाना रोड पर कार्यालय है। इसने कार्यालय में कई कर्मचारी काम भी करते हैं। इनकी सुरक्षा को देखते हुए, पहले ही पुलिस की ओर से सुरक्षा दी गई है।

4 जून की है घटना

पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि 4 जून को वह अपने पीएसओ के साथ कार्यालय में मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने एक युवक को कार्यालय की ओर आते देखा।

उसके हाथ में पिस्टल था। जिससे उसने उन पर दो बार गोली चलाने का प्रयास किया। लेकिन उसके पिस्टल गोली नहीं चली। यह देखकर कारोबारी ने पीएसओ को आवाज लगाई।

पीएसओ के बाहर आते ही बदमाश सड़क पर खड़े अपने सहयोगी की स्कूटी पर बैठकर बवाना की ओर भाग गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और कार्यालय और आस पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में कर लिया।

विदेशी नंबर से काल कर मांगी थी रंगदारी

कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो जून को उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से अनजान व्यक्ति ने फोन किया था। फोन करने वाले ने बताया कि गैंगस्टर संपत नेहरा ने उसका नंबर दिया है। कारोबारी ने बताया कि फोन करने वाले ने उनसे रंगदारी की मांग की। साथ ही पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद से पीड़ित परिवार डरा हुआ है।

तकनीकी जांच से आरोपित का पता लगा रही पुलिस

पुलिस अधिकारी का कहना है कि कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी में स्कूटी सवार बदमाश भागते हुए कैंद भी हुआ है। पुलिस इसके भागने की दिशा में सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस तकनीकी जांच के जरिए बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस मुखबिरों से भी बदमाशों का पता लगाने में जुटी है।

सावधान ! चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल, अब डेंगू ने दी दस्तक; तीन लोगों में मिली संक्रमण की पुष्टि

जिले में इस समय गर्मी से लोग परेशान हैं तो अब गर्मी के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। अभी तक तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग जारी है। 31298 घरों का सर्वे किया जा चुका है। अब तक 314 सैंपल लिए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में पनपता है

परिवहन विशेष न्यूज

जिले में इस समय गर्मी से लोग परेशान हैं तो अब गर्मी के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। अभी तक तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग जारी है। 31298 घरों का सर्वे किया जा चुका है। अब तक 314 सैंपल लिए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में पनपता है

गुरुग्राम। जिले में गर्मी के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को डीएलएफ सिटी फेज-2 और सेक्टर 53 स्थित गांधी नगर के तीन लोगों की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है।स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 31298 घरों का सर्वे किया जा चुका है। जबकि, 314 सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा डायरिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर-घर सर्वे जारी है। डेंगू के खतरे की आशंका को लेकर संदिग्ध लोगों की सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाव उपाय बताने के साथ-साथ कूलर, गमले, फ्रीज ट्रे, टायर, ट्यूब, नाद आदि हर छोटी-बड़ी जगह की भरे पानी को साफ करने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

सैंपल लेते स्वास्थ्यकर्मी

विशेषज्ञों की माने तो डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में पनपता है। इसका वाहक एडीज मच्छर है, जो दिन के समय काटता है। डेंगू के सामान्य मामलों में बुखार का चौथा से सातवां दिन बेहद खतरनाक होता है।

पहले दिन से लेकर पांच दिन तक सिर्फ एनएसवन टेस्ट पाजीटिव आता है, जबकि पांच दिनों के बाद एलाइजा टेस्ट पाजीटिव आता है।

विगत दो वर्षों से डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। गत वर्ष डेंगू के करीब 440 मामले सामने आए थे, जबकि डेंगू से एक मौत भी दर्ज की गई ।

इस बात का रहे ध्यान

अगर डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं तो चिकित्सक की निगरानी में इलाज करवाएं। खुद से चिकित्सा करने का प्रयास न करें। अगर किसी लैब में जांच के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा की वसूली की जा रही है तो भी स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें।

निजी अस्पतालों में टेस्ट के रेट निर्धारित

प्रदेश सरकार ने जिला में सभी प्राइवेट अस्पतालों तथा लैब में डेंगू व चिकनगुनिया की जांच के लिए 600 रुपये निर्धारित किये हैं। वहीं चिकनगुनिया के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1000 रुपये निर्धारित किये गए हैं।

डीएलएफ सिटी फेज-2 और सेक्टर 53 स्थित गांधी नगर के तीन लोगों की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। गुरुवार को टीम ने शहरी क्षेत्रों में 16128 और ग्रामीण क्षेत्रों में 15170 घरों का सर्वे किया। इसमें सात संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जबकि, छह लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 10 घरों में और 23 कंटेनरों में लार्वा मिला। इसे टीम ने मौके पर ही नष्ट किया।

डा. जयप्रकाश, जिला मलेरिया अधिकारी

14 साल से फरार 50 हजार के इनामी बदमाश को यूपी एसटीएफ ने दबोचा, दिल्ली पुलिस भी भेज चुकी जेल

दिल्ली-एनसीआर में चोरी के वाहनों को खंपाने वाले 50 हजार के इनामी बदमाश राजकुमार पांडेय को यूपी एसटीएफ ने आज बिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साथी संग चोरी के वाहन खपाता था। आरोपित के खिलाफ मुरादनगर थाने में 2010 मामला में दर्ज हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने उस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस 2009 में उसे जेल भेज चुकी है।

मोदीनगर। दिल्ली-एनसीआर में चोरी के वाहनों को खंपाने वाले 50 हजार इनामी बदमाश राजकुमार पांडेय को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ मुरादनगर थाने में 2010 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय आरोपित का साथी नगद नारायण गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस को चकमा देकर फरार : उसके कब्जे से चोरी की कार बरामद हुई थी। जबकि राजकुमार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तभी से पुलिस इसकी तलाश में थी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आरोपित पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया।अब मामला यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। मुखबिर की सूचना पर बिहार के पटना से आरोपित की गिरफ्तारी हुई।

आरोपित बिहार का रहने वाला : डीसीपी ग्रामीण विवेक चंद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित बिहार के थाना छपरा क्षेत्र स्थित गांव मजरिया का राजकुमार पांडेय(52) हैं। आरोपित ने 2001 से 2005 के बीच दवाइयों की सप्लाई का काम किया। इसी दौरान उसकी पहचान छपरा के नगद नारायण से हुई। उसने राजकुमार की मुलाकात दूर के रिश्तेदार लखनऊ के कर्नल एपमी सिंह से कराई।

तीनों ने चोरी के वाहन की खरीद-फरोख्त का काम किया शुरू: तीनों ने चोरी के वाहन की खरीद-फरोख्त का काम शुरू किया। पूर्वांचल के बाद इन्होंने अपने पैर दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में भी पसारने शुरू किये। वाहनों को चोरी कर उन्हें कम दामों में बेचने लगे। इसके बाद चोरी के वाहनों के पार्ट की बिक्री भी शुरू कर दी। आरोपित नगद नारायण व राजकुमार को 2009 में दिल्ली की कालकाजी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहां से जमानत पर आने पर आरोपितों ने क्षेत्र बदल दिया। मुरादनगर में चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त करने लगे। पुलिस 9Ghaziabad Police) ने 2010 में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी तो आरोपित नगद नारायण चोरी के वाहन के साथ पकड़ा गया। लेकिन राजकुमार फरार हो गया। नगर नारायण से पूछताछ में कई राज सामने आए।

गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना, संभाल चुके हैं ये तीन अहम मंत्रालय

लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और इस चुनाव में एनडीए को पूर्व बहुमत मिली है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधामंत्री पद की शपथ लेंगे। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इसी कड़ी में यूपी की गौतमबुद्ध नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉ. महेश शर्मा ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर हैट-ट्रिक बनाई। संभावना जताई जा रही है कि इन्हें मोदी कैविनेट में जगह मिल सकती है।

नोएडा। एक तरफ लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अब सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे।

वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से भाजपा के डॉ. महेश शर्मा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। उन्होंने इस चुनाव में जीत के साथ ही हैट्रिक लगाई है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि महेश शर्मा को इसका इनाम मिल सकता है। कुल मिलाकर कहें तो उन्हें मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Oath Ceremony)) में जगह मिलने की संभावना है।

यूपी में महेश शर्मा की मतों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत

गौतमबुद्ध नगर लोकसभा सीट (Gautam Buddh Nagar Lok Sabha Seat 2024) से भाजपा प्रत्याशी महेश शर्मा (Mahesh Sharma) ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर हैट-ट्रिक बनाई। 8,57,829 मत प्राप्त कर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी गठबंधन के सपा प्रत्याशी डा. महेंद्र नागर को 5,59,472 रिकार्ड मतों से हराया। यूपी में उनकी मतों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है।

डा. महेंद्र नागर को 2,98,357 मत मिले। बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 2,51,615 मत मिले। चौथे नंबर पर नोटा रहा। 10324 मतदाताओं ने नोटा पर बटन दबाया। गौतमबुद्ध नगर सीट पर डा. महेश शर्मा की यह अब तक की सबसे बड़े अंतर से जीत है। उन्हें कुल पड़े मतों का 59.69 प्रतिशत मत मिले।

भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक

वह भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। पहली बार वो साल 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनावों में निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल की। 17वें लोकसभा चुनावों में डॉ. शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के प्रत्याशी सतबीर नागर को कुल 3,36,922 वोटों के अंतर से हराया था।

संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का मिल चुका जिम्मा

पेशे से चिकित्सक रहे डॉ. महेश शर्मा संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रह चुके हैं। इसके साथ ही वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे यूपी से विधायक के रूप में भी चुने जा चुके हैं।

राम नगरी अयोध्या में आखिर किन कारणों से हारी भाजपा ?

आचार्य डॉ राधे श्याम द्विवेदी

कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली के रास्ते में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा अवरोध लखनऊ बन गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में अयोध्या में अपनी पकड़ कायम ना रख सकी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी टाट-पट्टी में रहते थे तो बीजेपी अयोध्या में राम की गरिमा मय देवत्थान बनाने के संकल्प को लेकर दो सदस्य संख्या को बढ़ाते-बढ़ाते कई बार प्रदेश और केंद्र में अपना बहुमत बना कुशल पूर्वक सरकार चलाई थी। वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जैसे कुशल प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री को जनता की सेवा का अवसर पाने में अयोध्या की पुनर्स्थापना में महत्व पूर्ण भूमिका रही। देश प्रदेश तथा अंतराष्ट्रीय जगत में इस प्रकरण को बहुत ही अहमियत मिली, परन्तु 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने अपनी स्थिति बरकरार बनाए रखने में विफल रही । उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी फैजाबाद-अयोध्या लोकसभा सीट तथा उससे लगे हुए अंबेडकर नगर, बस्ती, खलीलाबाद सुलतानपुर, अमेठी, रायबरेली और गोंडा आदि पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यूपी के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए। एक बार पहले भी आए थे तब ये कामयाब नहीं हो सके थे लेकिन इस बार की अपने मकसद में कामयाब होते देखे जा रहे हैं। भाजपा पिछले एक दशक में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारणों और परिस्थितियों पर एक बार विहंगम दृष्टि डालना अनुचित ना होगा।

> **बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव-प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया।**

चुनाव हारने के प्रमुख कारण:-

1.माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अतिसक्रियता:-

जब देश और प्रदेश के मुखिया जहां ज्यादा सक्रिय रहेंगे वहां स्थानीय सांसद और विधायक की पकड़ ढीली हो जायेगी। वह लोगों में अपनी इमेज नहीं बना पाएगा। वह आम जनता से दूर होता जायेगा। इस कारण एसटी स्थानीय सांसद और विधायक अपना कर्तव्य बखूबी से निभाने में विफल रहे।

2. पुराने जन प्रतिनिधियों का सहयोग ना ले पाना:-

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अयोध्या आंदोलन के प्रणेता माननीय आडवाणी जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, रितंभरा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी आदि का सहयोग नहीं लिया गया। सब कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सक्रियता के कारण अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन ना कर सके।

3. विकास योजनाएं जनता को पसन्द नहीं:-

अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों की विकास योजनाओं को पूरा कराया गया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया था। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विकास किया गया। अयोध्या रामलला मंदिर के साथ-साथ सड़कों से लेकर गलियों तक को दुरुस्त किया गया। अयोध्या में विकास करना कोई काम नहीं आया। अयोध्या में 2017 के बाद से हर साल दिवाली पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों का भी प्रभाव नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने अयोध्या आए। कोरोना के खतरे के बीच रामलला का मुद्दा देश भर में गरमाया। 22 जनवरी को इस साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस समारोह में भाग लेने पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनके साथ-साथ देश भर से विशिष्ट लोगों का यहां आगमन हुआ। ये सब जन आयोजन ना होकर सरकारी आयोजन बन गए।

4. राम लहर काम ना आई:-

राम मंदिर का मुद्दा वैसे तो पूरे देश के लिए अहम था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से कुछ सीटों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब फैजाबाद सीट तो केंद्र में थी ही, इसके अलावा गोंडा, कैसरगंज, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, बस्ती सीट पर भी राम मंदिर का काफी प्रभाव था। यह सारी सीटें फैजाबाद के आसापास ही पड़ती हैं, ऐसे में माना जा रहा था यहां से बीजेपी को ज्यादा चुनौती नहीं रही। इस क्षेत्र के चुनावी नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। जिस अयोध्या को लगातार राम नगरी कहकर संबोधित किया गया, जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने राम के नाम पर वोट मांगा, उसी सीट को राम विरोधी समाजवादी पार्टी ने हथिया लिया है।

5. ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, फोकस सिर्फ अयोध्या धाम पर:-

बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव-प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया।

6. जमीनों का अधिग्रहण:-

अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। कई लोगों के घर-दुकान तोड़े गए। निराशाजनक पहलू यह रहा कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में घर-दुकान तोड़े गए लेकिन प्रभावितों को उचित नहीं मिला।

7. प्रत्याशी को एंटी इन्कंबैंसी का असर:-

निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह के खिलाफ क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर थी। लोगों की नाराजगी उनके क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर थी। उम्मीदवार से लोगों की नाराजगी उन्हें ले डूबी। उम्मीदवार के प्रति यह गुस्सा लोगों के भीतर बदलाव के रूप में उभरने लगा। वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े मठों से तो जुड़े पर छोटे तपकों से दूर होते गए।

स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह के प्रति लोगो की बहुत नाराजगी रही। बीजेपी हाई कमान ने सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा था। यह निर्णय लोगों को अनुकूल ना लगा। भाजपा उम्मीदवार लगातार 10 साल से सांसद थे। उनको बदले जाने का दबाव स्थानीय स्तर के नेताओं की ओर से भी बनाया जा रहा था। इसके बाद भी भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नया चेहरा ना उतरना ही बीजेपी को यहां भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों को नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजतन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव-प्रचार के दौरान संविधान बदलने का बयान भी दिया था। बयान पर काफी हो-हल्ला मचा था।

8. आवारा पशु को लेकर नाराजगी: -

अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आवारा पशुओं से खासे परेशान रहे हैं। सरकार ने गोशाला जरूर बनाई हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाल पाई है। आवारा पशुओं के मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया था। बीजेपी को इस मुद्दे पर नाराजगी झेलनी पड़ी और हार का दंश झेलना पड़ा।

9. जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार उतरना:-

जातीय समीकरण को साधने में भाजपा सफल नहीं हो पाई। अखिलेश यादव इस सीट पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए को एकजुट करने में सफल हो गए। यह भाजपा की हार का कारण बन गई। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए मंदिरों के इस शहर से एक दलित को उम्मीदवार बनाया था। उसकी यह रणनीति काम कर गई ।

10. जातिगत समीकरण हावी :-

अयोध्या के जानकारों के मुताबिक जातिगत समीकरण और अयोध्या के विकास के लिए जमीनों का अधिग्रहण को लेकर जनता में जबरदस्त नाराजगी है। इसके साथ ही कांग्रेस का आरक्षण और संविधान का मुद्दा काम कर गया। लल्लू यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो संविधान में बदलाव के लिए बीजेपी को 400 से अधिक सीटें जिताने की बात कर रहे थे। वहीं बसपा का कमजोर होना भी सपा की बढ़त में बड़ा काम किया।

11. मुस्लिम वोटरो की एकजुटता

कांग्रेस-सपा के जिस गठबंधन को 2017 में नहीं चल पाया था, वह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जमकर वोट बटोरे हैं। उत्तर प्रदेश के जानकारों के मुताबिक इस चुनाव में मुस्लिम वोट ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया। संविधान और आरक्षण बचाने के मुद्दे को हवा देकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के कोर हिंदू वोट बैंक को भी बांट दिया। विपक्ष के इस नैरेटिव ने बड़ी संख्या दलितो, पिछड़ों और आदिवासियों को बीजेपी से दूर किया। महंगाई और बेरोजगार के मुद्दे ने भी का मुद्दा भी काम करता दिखा।

12. बड़े शीर्षस्थ नेताओं के कारण ओवर कॉफिडेंस:-

भाजपा यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। बीजेपी ने माना कि उम्मीदवार के चेहरे की जगह अयोध्या में पीएम मोदी का चेहरा चलेगा। यह सफल नहीं हो पाया।

13. स्थानीय सांसद द्वारा जमीन का खरीद फरोख्त:-

स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन खरीद और फिर उसे ऊंचे दामों में बेचने का आरोप लगा हुआ है। श्रीराम मंदिर पर फैसले के बाद जमीन खरीद-बिक्री का मामला जोर-शोर से उठा था। इस पर बड़ा जोर दिया गया। इससे लल्लू सिंह की छवि धूमिल हुई और उन्हें कम वोट मिले।

(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा मंडल ,आगरा में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए समसामयिक विषयों, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं।)

हीटवेव में कूल रखना है कार का इंजन, तो अपनाएं ये तरीका; जानिए जरूरी चीजें

परिवहन विशेष न्यूज

कार के इंजन को ज्यादा गरम होने से बचाने के लिए फ्लुइड को उचित मात्रा में रखने की जरूरत है। इसलिए नियमित रूप से इंजन कूलेंट लेवल की जांच करें और गर्मी शुरू होने से पहले निर्माता द्वारा सुझाए गए कूलेंट से इसे ऊपर तक भरें। स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस अपनाने से चिलचिलाती गर्मी के दौरान आपकी कार के तापमान को प्रबंधित करने में काफी मदद मिल सकती है।

नई दिल्ली। समूचे देश में गर्मी का कहर है और लोग लगातार बढ़ रहे पारे के चलते काफी परेशान हैं। देश के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, सामान्य जीवन के लिए काफी ज्यादा कष्टदाई है। ऐसे में हमे अपने शरीर के साथ-साथ गाड़ियों की भी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। भरी गर्मी में भी आपकी कार ठंडी रहे और सुचारू रूप से चले, इसके लिए आप नीचे दी गई चीजों का ध्यान रखें।

सही जगह पार्किंग

सही पार्किंग स्थान खोजना आपकी कार को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी संभव हो, इंजन कम्पार्टमेंट पर निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए इसे छायादार स्पेस में ही पार्क करें।

इंजन कूलेंट लेवल की जांच

कार के इंजन को ज्यादा गरम होने से बचाने के लिए फ्लुइड को उचित मात्रा में रखने की जरूरत है। इसलिए, नियमित रूप से इंजन कूलेंट लेवल की जांच करें और गर्मी शुरू होने से पहले निर्माता द्वारा सुझाए गए कूलेंट से इसे ऊपर तक भरें। अगर इसे बार-बार टॉप-अप करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि लीकेज की समस्या हो। इसके लिए आपको मैकेनिक को दिखाना होगा।

ड्राइविंग स्टाइल में बदलाव

स्मार्ट ड्राइविंग प्रैक्टिस अपनाने से चिलचिलाती गर्मी के दौरान आपकी कार के तापमान को प्रबंधित करने में काफी मदद मिल सकती है। अपनी कार को ओवरलोड करने से बचें। खासकर लंबी यात्राओं पर ऐसा न करें। अतिरिक्त वजन से इंजन पर दबाव और ऑपरेटिंग तापमान बढ़ाता है।

टाटा अल्ट्रॉज रेसर इंडियन मार्केट में लॉन्च, केवल 9.49 लाख रुपये में मिलेगी स्पोर्टी परफॉरमेंस वाली कार

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स ने भारत में नई Altroz Racer लॉन्च की है। टाटा अल्ट्रोज रेसर में किए गए कॉस्मेटिक अपग्रेड में डुअल-टोन पेंट स्कीम के लिए ब्लैक-आउट बोनट और रूफ शामिल हैं। कार में बोनट रूफ और बूट पर व्हाइट स्ट्रिप है। टाटा अल्ट्रोज रेसर में सबसे बड़ा अपडेट इसका नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो टाटा नेक्सन से लिया गया है।

नई दिल्ली। Tata Motors ने भारत में नई Altroz Racer लॉन्च की है, जिसकी कीमत 9.49 लाख रुपये से शुरू होकर 10.99 लाख रुपये (शुरुआती, एक्स-शोरूम) तक है। नई टाटा अल्ट्रोज रेसर टर्बो पेट्रोल पर आधारित ज्यादा परफॉरमेंस-ओरिएंटेड वर्जन है।

डिलीवरी डिटेल

कंपनी ने इसकी अपील को और बढ़ाने के लिए इसमें स्पोर्टी एस्थेटिक अपग्रेड किए गए हैं। अल्ट्रोज रेसर की बुकिंग 21,000 रुपये के टोकन पर शुरू हो गई है। अल्ट्रोज रेसर के अलावा, टाटा ने स्टैंडर्ड अल्ट्रोज के चुनिंदा वेरिएंट को और ज्यादा फीचर्स के साथ अपडेट भी किया है।

डिजाइन अपडेट

टाटा अल्ट्रोज रेसर में किए गए कॉस्मेटिक अपग्रेड में डुअल-टोन पेंट स्कीम के लिए ब्लैक-आउट बोनट और रूफ शामिल हैं। कार में बोनट, रूफ और बूट पर व्हाइट स्ट्रिप है। नए वर्जन में स्पोर्टी ट्रीटमेंट के लिए नए एलॉय व्हील के साथ फेंडर पर 'रेसर' बैज भी मिलेगा। अल्ट्रोज रेसर तीन डुअल-टोन रंगों - एटॉमिक ऑरेंज, एवेन्यू व्हाइट और प्योर ग्रे में उपलब्ध है।

फीचर्स और इंटीरियर

केबिन में नारंगी हाइलाइट्स के साथ ब्लैक-आउट प्रजेंस, कंट्रास्ट स्टिचिंग और ट्विन स्ट्राइप्स के साथ ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। डैशबोर्ड वही रहता है, लेकिन मॉडल में इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, क्रूज कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं। टाटा अल्ट्रोज रेसर मुख्य रूप से सेगमेंट में Hyundai i20 N Line को टक्कर देगी।

इंजन और स्पेसिफिकेशन

टाटा अल्ट्रोज रेसर में सबसे बड़ा अपडेट इसका नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो टाटा नेक्सन से लिया गया है। यह मोटर 118 बीएचपी और 170 एनएम का पीक टॉर्क देता है, जिसे केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध नहीं है। टाटा का यह भी कहना है कि मॉडल में स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट है।

रॉयल इन्फील्ड ने ट्रेडमार्क कराए 2 नए ब्रांड लॉगो, जानिए कहां हो सकता है इनका इस्तेमाल

रॉयल एनफील्ड ने पिछले कुछ सालों में Made Like A Gun बैज से लेकर RE एंबल तक कई ब्रांड लोगो को ट्रेडमार्क किया है जो अलग-अलग उपयोग के मामलों पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि कंपनियां लोगो नाम और बहुत कुछ ट्रेडमार्क करती हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वे हमेशा वही इस्तेमाल करें। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Royal Enfield ने हाल ही में दो नए ब्रांड लोगो के लिए ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए हैं। एक लोगो पुराने जमाने का डिजाइन है, जिसके ऊपर मुकुट बना हुआ है। वहीं, दूसरा Royal Enfield अक्षर का स्टाइलिश वर्जन है। हालांकि, कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह इन लोगो का इस्तेमाल कहां करने की योजना बना रही है, लेकिन यह काफी संभावना है कि ब्रांड की आने वाली मोटरसाइकिलों में इनमें से किसी एक का उपयोग किया जाएगा।

कहां काम आएगा नया लोगो?

रॉयल एनफील्ड ने पिछले कुछ सालों में Made Like A Gun बैज से लेकर RE एंबल तक कई ब्रांड लोगो को ट्रेडमार्क किया है, जो अलग-अलग उपयोग के मामलों पर निर्भर करता है। नए ब्रांड लोगो भी इसी ओर इशारा करते हैं। पुराने जमाने का लोगो फ्यूल टैंक या इंजन केसिंग पर बैज के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि स्टाइलिश लोगो का इस्तेमाल निर्माता के अपैरल, एक्सेसरीज और राइडिंग गियर पर किया जा सकता है।

अमूमन ये भी करती हैं कंपनियां

आपको बता दें कि कंपनियां लोगो, नाम और बहुत कुछ ट्रेडमार्क करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे हमेशा वही इस्तेमाल करें। यह रॉयल एनफील्ड के नए लोगो के साथ भी सच हो सकता है, जो हमेशा मोटरसाइकिल पर नहीं हो सकता है, लेकिन निर्माता से संचार के अन्य रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

RE की फ्यूचर प्लानिंग

ब्रांड की ओर पहले से ही कई नए प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है। इनमें से एक Guerrilla 450 और दूसरा Classic 650 हो सकता है, जिसे हमने कई बार परीक्षण के दौरान देखा है। इसलिए, शायद बैजिंग प्रारूप का उपयोग मिडिलवेट क्लासिक के लिए किया जा सकता है।

हालांकि, रॉयल एनफील्ड अपने परिधान, एक्सेसरीज़ और यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर अलग-अलग लोगो का उपयोग करता है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ब्रांड के अन्य उत्पादों के लिए दो में से एक या दोनों लोगो का उपयोग किया जाए।

महिन्दरा BE.05 टेस्टिंग के दौरान फिर आई नजर, अगले साल होगी लॉन्च

Mahindra BE.05 ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी को हाल ही में मुंबई में हैवी कैमोफ्लेग के साथ देखा गया है। जैसा कि ब्रांड ने पहले पुष्टि की है ऑल-इलेक्ट्रिक BE.05 को भारतीय बाजार में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा के लेटेस्ट INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी BE.05 इलेक्ट्रिक SUV 2WD और 4WD पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी। Mahindra BE.05 में LFP सेल के साथ 79 kWh का बैटरी पैक मिलेगा।

नई दिल्ली। Mahindra की ओर से भारतीय सड़कों पर आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV.e8, XUV.e9 और BE.05 को टेस्ट किया जा रहा है। Mahindra BE.05 ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी को हाल ही में मुंबई में हैवी कैमोफ्लैग के साथ देखा गया है। हाल ही में ली गई स्पाई तस्वीरों में BE.05 प्रोडक्शन-रेडी लग रही है, जिसमें कुछ बाहरी विवरण भी शामिल हैं।

Mahindra BE.05 का डिजाइन

जैसा कि ब्रांड ने पहले पुष्टि की है, ऑल-इलेक्ट्रिक BE.05 को भारतीय बाजार में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में ली गई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि फ्रंट फेसिया में ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल, बड़े एयर इनटेक और लाइट बार के माध्यम से जुड़े स्लीकर-लुकिंग LED DRLs होंगे।

साइड प्रोफाइल में चौकोर व्हील आर्च हैं, पिलर पर रियर डोर हैंडल लगे हैं और ढलान वाली रूफ लाइन है। BE.05 में पीछे की तरफ चंकी रियर बंपर, स्प्लिट रियर स्पॉइलर, टर्न इंडिकेटर्स के साथ C-शेप्ड LED टेल-लैंप और रेक्ड विंडस्क्रीन है।

इंटीरियर

इससे पहले की स्पाई तस्वीरों में महिंद्रा BE.05 के केबिन का खुलासा हुआ है। इसमें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, इल्यूमिनेटेड 'BE' लोगो के साथ ट्विन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और इंस्ट्रूमेंट पैनल के लिए डुअल-स्क्रीन सेटअप होगा। इसके अलावा, इसमें नए डिजाइन किए गए ग्रैब हैंडल होंगे।

बैटरी, मोटर और पावरट्रेन

महिंद्रा के लेटेस्ट INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी BE.05 इलेक्ट्रिक SUV 2WD और 4WD पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध होगी। 2WD मॉडल में Volkswagen से ली गई रियर एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 286 hp की अधिकतम पावर और 535 Nm का अधिकतम टॉर्क देती है।

वहीं, 4WD वेरिएंट में फ्रंट-एक्सल माउंटेड मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 109 hp की पावर और 135 Nm का टॉर्क देगी। चूंकि इस वेरिएंट में डुअल मोटर सेटअप का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए संचयी सिस्टम आउटपुट अभी पता नहीं चल पाया है।

Mahindra BE.05 में LFP सेल के साथ 79 kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो सिर्फ आधे घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा। लॉन्च होने पर BE.05 को XUV400 इलेक्ट्रिक एसयूवी के ऊपर रखा जाएगा। भारतीय बाजार में Tata Curvv EV को टक्कर देगी।

किआ EV3 के ग्लोबल लॉन्च के बाद कीमतों का हुआ खुलासा, जानिए भारतीय बाजार में कब मारेगी एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

किआ EV3 अगस्त 2024 तक कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी उसके बाद यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भी ये एंट्री मारने वाली है। भारत में लॉन्च 2025 में होने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो इसमें टाइगर-नोज से इंस्पायर्ड फेसिया के साथ ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और निचले बम्पर में चौड़े एयर इनलेट हैं। इसमें L-आकार के LED DRLs के साथ क्यूबिकल-आकार के LED हेडलैंप हैं।

नई दिल्ली। Kia ने अक्टूबर 2023 में आयोजित किए गए EV Day पर Kia EV3 electric SUV का कॉन्सेप्ट शोकेस किया था। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल लॉन्च करने बााद इसके दामों की भी घोषणा कर दी है।

Kia EV3 में क्या खास?

Kia EV3 अगस्त 2024 तक कोरिया में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, उसके बाद यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में भी ये एंट्री मारने वाली है। भारत में लॉन्च 2025 में होने की उम्मीद है। लॉन्च होने पर यह सीधे BYD Atto 3 और इसी तरह की कीमत वाली अन्य इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर देगी।

Kia EV3 की कीमत

दक्षिण कोरिया में कीमतों की बात करें तो, एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत KRW 42.08 मिलियन (मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग 25.60 लाख रुपये) है। अर्थ वेरिएंट की कीमत KRW 45.71 मिलियन (मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग 27.80 लाख रुपये) और टॉप-ऑफ-द-लाइन GT-लाइक और लॉन्ग-रेंज वेरिएंट की कीमत KRW 46.66 मिलियन (मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग 28.37 लाख रुपये) है।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें, तो इसमें टाइगर-नोज से इंस्पायर्ड फेसिया के साथ ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और निचले बम्पर में चौड़े एयर इनलेट हैं। इसमें L-आकार के LED DRLs के साथ क्यूबिकल-आकार के LED हेडलैंप हैं।

साइड में EV3 में मोटे काले प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ फ्लेयर्ड व्हील आर्च और आगे और पीछे के फेंडर पर ट्रेपोजॉइडल क्रीज हैं।

पीछे की तरफ, इसमें दोनों छोर पर फैले L-आकार के LED टेललैंप के साथ एक बोल्ड टेलगेट है। अन्य हाइलाइट्स में ब्लैक क्लैडिंग, रूफ स्पॉइलर, शार्क-फिन एंटीना और बहुत कुछ शामिल हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

Kia EV3 के डैशबोर्ड लेआउट में 2 मेन स्क्रीन- इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट के लिए 12.3-इंच यूनिट है। इसमें डैशबोर्ड की चौड़ाई में चलने वाले स्लीक AC वेंट हैं और साथ ही एक साफ-सुथरे डिजाइन वाला टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12 इंच का हेड-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, पर्सनल AI असिस्टेंट, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto, वायरलेस चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, कप होल्डर के साथ फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, कार चार्ज होने के दौरान इंफोटेनमेंट यूनिट पर वीडियो या गेम की स्ट्रीमिंग के साथ रिलैक्सेशन मोड और बहुत कुछ है।

पावरट्रेन, बैटरी और मोटर

पावरट्रेन और बैटरी की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिक कार 2 बैटरी पैक- 58.3 kWh और 81.4 kWh के साथ उपलब्ध है। यह फ्रंट-एक्सल माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है, जो 201hp और 283Nm का टॉर्क देता है। इसने 7.5 सेकंड में 0-100kph स्प्रिंट टाइम और 170kph की टॉप स्पीड का दावा किया है। 81.4 kWh वाले लॉन्ग-रेंज वैरिएंट की दावा की गई रेंज 600 किमी WLTP साइकिल है और बैटरी को 31 मिनट में 10 से 80 तक चार्ज किया जा सकता है।

मोदी अपना मनोबल गिरने नहीं देंगे

जूलियो रिबैरो

नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल मिला। जैसा कि एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी, यह कोई आसान काम नहीं था। भाजपा अपने दम पर 272 के आंकड़े से काफी कम 240 सीटें ही हासिल कर पाई। उसे शासन करने के लिए एन.डी.ए. (राजग) में...

नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल मिला। जैसा कि एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी, यह कोई आसान काम नहीं था। भाजपा अपने दम पर 272 के आंकड़े से काफी कम 240 सीटें ही हासिल कर पाई। उसे शासन करने के लिए एन.डी.ए. (राजग) में अपने सहयोगियों को समायोजित करना होगा। तेदेपा, जद-यू और अन्य ने मिलकर 54 सीटें हासिल कीं जिससे मोदी के लिए कैबिनेट पोर्टफोलियो आबंटित करने में समस्या पैदा हो गई।

एन.डी.ए. जिसमें वे पार्टियां शामिल हैं जिनके पास भाजपा के साथ गठबंधन की चुनाव पूर्व समझ थी, ने 294 सीटें हासिल कीं, जो कि मोदी द्वारा गठबंधन के लिए निर्धारित 400 के आंकड़े से 100 से अधिक कम है। मोदी अब भी देश के सबसे सक्षम राजनीतिक नेता हैं लेकिन उनका दबदबा कम हो गया है। उन्हें शासन की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, विशेषकर वह राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह देखने वाली बात होगी।

मोदी ने चुनावी जीत हासिल करने के लिए हदू बहुमत बनाम मुस्लिम अल्पसंख्यक कार्ड का इस्तेमाल किया। यह 2014 और 2019 में काम आया। लेकिन इस संशोधित जनादेश के साथ उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। स्पष्ट रूप से यह अब विजेता नहीं हैं। उन्हें संघ परिवार में सीमांत तत्वों को अनुशासित करने की जरूरत है। उन्हें वश में करने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। एक बार जिन्न के बाहर आने के बाद उसे दोबारा बोतल में बंद करना आसान नहीं है।

मोदी को अपनी मुख्य प्राथमिकता के रूप में नौकरियों और बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने तीसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली और सबसे बड़ी ङ्क्षचता होनी चाहिए। भारतीय मतदाताओं ने जो कठोर संदेश दिया है, उसके आलोक में इन सभी को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। मोदी को बुनियादी बातों-शिक्षा और स्वास्थ्य से शुरूआत करनी होगी। यहां उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सबक लेना चाहिए। उस पार्टी ने इन दोनों क्षेत्रों में बड़ी सेंध लगाई है। जब तक हमारी श्रम शक्ति की उत्पादकता कई गुना नहीं बढ़ जाती, हम अपने पूर्व के पड़ोसी की बराबरी नहीं कर पाएंगे, जिसने हमसे 50 साल या उससे अधिक का सफर तय किया है। मोदी को 'शहरी नक्सली' कहे जाने वाले लोगों के प्रति अपनी नापसंदगी को भी कम करने की जरूरत है। उनमें से अधिकांश संपन्न परिवारों से आते हैं, लेकिन उनमें गरीबों और वंचितों के लिए बहुत अधिक ङ्क्षचता विकसित हो गई है।

भाजपा के साथ अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल करने में विफल रहने पर स्थिरता का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। चंद्र बाबू नायडू की तेदेपा और नीतीश कुमार की जद-यू भाजपा की ङ्क्षहदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं हैं। अब जिस चीज की आवश्यकता है वह मेरे द्वारा पहले बताई गई पंक्तियों पर सुधार की है। एक राजनेता के लिए उपयुक्त गुणों वाले 'जीवन भर में एक' नेता के रूप में उनकी तेजी से लुप्त होती प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए यह सुधार आवश्यक है।

वर्तमान में, उनके कट्टर अनुयायियों के बीच उनका कद दैवीय गुणों वाले एक महामानव जैसा है। दुर्भाग्य से उनके आलोचक, जो काफी संख्या में हैं, उन्हें बिल्कुल अलग रंग के चश्मे से देखते हैं। विदेश में वैश्विक नेताओं के साथ उनकी स्थिति ऐसी है जिसे उनके देश की बढ़ती आर्थिक ताकत के कारण 'हम नजरअंदाज नहीं कर सकते'। फिर भी वे उन्हें मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार के बारे में लगातार याद दिलाते रहते हैं। उसे धीरे से धक्का देने वालों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब उनके ताकतवर होने की संभावना है क्योंकि उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन एक साथ आया था। वे जानते थे कि जब वह निर्वाचित नेता के रूप में अपनी सुविधाजनक स्थिति से शासन करेंगे, तो संभावना है कि वह उन्हें एक-एक करके कुचल देंगे, जैसे उन्होंने अपनी पार्टी में पुराने नेताओं को निपटा दिया था और आने वाले नेताओं को अनुमान लगाकर रखा था। मोदी जन्मजात नेता हैं जिनमें जीवित रहने की तीव्र प्रवृत्ति है। वह इस 'हार' से अपना मनोबल गिरने नहीं देंगे। मोदी ने विपक्ष को चेतावनी दी थी कि चुनाव में हार के बाद 'इंडिया' गठबंधन हवा में उड़ जाएगा।

इन नेताओं को मोदी की अपनी बुद्धिमत्ता से प्रेरणा लेते हुए सकारात्मक सोचना चाहिए। उन्होंने एक बहादुरी भरी लड़ाई लड़ी है और उन्हें इस हार को हार के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने घोर गलत अनुमान के रूप में एन.डी.ए. की भारी जीत की मोदी और शाह की भविष्यवाणी को खारिज कर दिया है। इसे 2 महान नेताओं के चेहरे पर तमाचे के रूप में भी समझा जा सकता है। भाजपा को भारतीय लोगों का केवल 37 प्रतिशत समर्थन प्राप्त है। एन.डी.ए. सामूहिक रूप से 41 प्रतिशत पर थोड़ा बेहतर है। भारतीय मतदाताओं का बहुमत मोदी और उनकी विचारधारा के साथ नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 'इंडिया' गठबंधन को अस्तित्व के लिए एकजुट रहने की जरूरत है।

एक समय महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे शरद पवार ने भविष्यवाणी की थी कि 'इंडिया' गठबंधन में छोटे दल भी शामिल होंगे। गठबंधन का कांग्रेस में विलय होगा। व्यक्तिगत रूप से, मुझे संदेह है कि क्या ऐसा होगा। यह लोकसभा चुनाव इतिहास में भारतीय चुनावों के सबसे लंबे और सबसे हंगामेदार चुनावों के रूप में दर्ज किया जाएगा। पूरे देश को कवर करने में 6 सप्ताह क्यों लगने चाहिएं? 3 या अधिक से अधिक 4 से काम चल जाएगा। मतदान के अंतिम दिन के अगले दिन वोटों की गिनती की जाती थी। इस बार इसकी तारीख 4 जून तय की गई थी। हालांकि मतदान का आखिरी दिन 1 जून था। इससे मतदाता अनावश्यक रूप से बेचैन हो गए।

चुनाव आयोग को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से अधिकतर अनावश्यक थीं, लेकिन कुछ इसके योग्य भी थीं। प्रधानमंत्री पर लगाम लगाने में उसकी हिचकिचाहट थी। अगर मोदी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट की सलाह मानी होती और सी.जे.आई. को शामिल किया होता तो चुनाव आयोग सदस्यों के चयन की प्रक्रिया में एक स्वतंत्र रैफरी के रूप में शायद ई.वी.एम. की अखंडता पर व्यर्थ सवाल नहीं उठाए गए होते।

(पूर्व डी.जी.पी. पंजाब व पूर्व आई.पी.एस. अधिकारी)

संपादक की कलम से

न तुम जीते न वह हारे!

यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत दुनिया में लोकतंत्र का मसीहा है। समूची दुनिया मानती है कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र कम ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने वाले मतदाताओं ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिससे समूची दुनिया अचंभित है।

यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत दुनिया में लोकतंत्र का मसीहा है। समूची दुनिया मानती है कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र कम ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने वाले मतदाताओं ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिससे समूची दुनिया अचंभित है। निश्चित रूप से नतीजों ने इतना तो बता दिया कि भारत का मतदाता खामोश भले ही रहे लेकिन फैसले वही करता है जो देश हित में जरूरी समझता है। यकीनन 2024 के खंडित जनादेश से अपने बलबूते बहुमत तक नहीं पहुंची भाजपा जहां 63 सीटें हारने के बावजूद ज्यादा सीटें जीतकर भी खुश नहीं है वहीं एक दशक के इंतजार के बावजूद 99 पर अटकी कांग्रेस भी गमजदा नहीं है। देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर आ गया है। नतीजों के बाद कहीं न कहीं बेहद पुराने सहयोगियों अकाली दल को खोने तो शिवसेना को 2 भागों में कराने का भी भाजपा के धुरंधरों को मलाल होगा। वहीं तमाम सहयोगियों से पिछले 10 वर्षों में किया गया बर्ताव और अब उन्हीं के सहारे सरकार चलाना कितना मददगार होगा? सबसे बड़ा सवाल यही चर्चाओं में है कि क्या मीट, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा जैसे बयान फिर सुनने को मिलेंगे? जबकि किसान आंदोलन, जबरदस्त महंगाई-बेरोजगारी, पेपरलीक जैसे अछूते मुद्दों ने भी चुनाव को प्रभावित किया। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में तो अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में भाजपा की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले घटी है। लोकसभा में जीत से उत्साहित नीतीश 6 महीनों के अंदर बिहार में चुनाव के पक्षधर होकर कई मांगें रखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा से लेकर अधिक मदद का दबाव होगा। उनकी सफलता का असर बिहार में निश्चित दिखेगा। ऐसे में इन विधानसभा चुनावों के बाद की राजनीति की करवट क्या होगी? अब नीतीश का बार-बार पाला बदलना अचरज के बजाय अवसर कहलाता है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री के पद से मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था। कुछ बीती कुछ हालिया बातें राजनीतिक भविष्य को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में मोदी का दिया वह भाषण विपक्ष काफी प्रचारित कर रहा है जिसमें चंद्रबाबू को अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया था। 2018 में नायडू ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर ही एन.डी.ए. छोड़ अपने 2 केन्द्रीय मंत्रियों को भी हटाया था।

लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहां न कोई स्थायी दोस्त होता है न ही दुश्मन। फिलहाल नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यह सच है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी गठबंधन सरकार नहीं चलाई। अब 2 शहजादों के चलते बने मजबूत विपक्ष और संविधान में आस्था रखने की दुहाई के नाम पर विपक्षी एकजुटता के आगे बहुमत से दूर मिली-जुली भाजपा-एन.डी.ए. सरकार चलाना और पहले जैसी मजबूती बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। सारे सवाल भविष्य के गर्त में छुपे हैं। लेकिन सबसे अहम यह कि अब की बार मोदी की एन.डी.ए. सरकार के काम और फैसलों की रफ्तार वैसी ही होगी जो बीते 2 कार्यकाल में थी? कम से कम मंत्रिमंडल गठन तक कयासों के संकेत का इंतजार करना होगा। 2014 के चुनावों में 282, 2019 में 303 सांसदों के मुकाबले इस बार भाजपा के 240 बनाम गठबंधन के 53 सांसदों के बीच मंत्रिमंडल संतुलन भी देखने लायक होगा। आक्रामकता के साथ चौंकाने वाले फैसलों की खातिर पहचान बना चुके नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे जिन्होंने 6130 दिन तक केंद्रीय सत्ता संभाली।

राय

चुनाव के नतीजे आर्थिक मुद्दों के महत्व की ओर इशारा करते हैं

लोकसभा चुनाव के नतीजे उन लोगों के लिए एक झटके के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने समस्याग्रस्त एग्जिट पोल पर गलती से विश्वास कर लिया था, जो कि मोदी सरकार द्वारा इतनी मेहनत से तैयार की गई कहानी को जारी रखता है। कई राजनीतिक पंडितों ने उन झूठी...

लोकसभा चुनाव के नतीजे उन लोगों के लिए एक झटके के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने समस्याग्रस्त एग्जिट पोल पर गलती से विश्वास कर लिया था, जो कि मोदी सरकार द्वारा इतनी मेहनत से तैयार की गई कहानी को जारी रखता है। कई राजनीतिक पंडितों ने उन झूठी भविष्यवाणियों को साहसपूर्वक सही ठहराया है। हम वास्तविक परिणामों की व्याख्या करने के लिए पहले ही कूद पड़े। एक मुख्य व्याख्या यह है कि 'इंडिया' गठबंधन ने सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर जोर दिया और अधिक चतुर गठबंधन बनाए रखा। जाति के संदर्भ में उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट विकल्प भी गठबंधन ने बनाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता की मान्यता और साथ ही संविधान के अस्तित्व के बारे में आशंकाएं महत्वपूर्ण कारक थीं। साहसी राज्यों में स्थानीय कारकों ने भी भूमिका निभाई होगी। अगली सरकार बनने पर उसे मतदाताओं के स्पष्ट संदेश को पहचानना होगा। आर्थिक मुद्दों का महत्व, बेरोजगारी और लगातार कम मजदूरी, स्व-रोजगार से अपर्याप्त आजीविका और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के प्रमुख संकटों को चुनावों के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। ये मुद्दे देश के अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां 'इंडिया' गठबंधन, खासकर कांग्रेस द्वारा किए गए वायदे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के कुछ हिस्सों में। विपक्षी पार्टियों ने सामाजिक न्याय के साथ-साथ आजीविका और रोजगार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके वायदे निःसंदेह अधिकांश मतदाताओं के बीच प्रतिध्वनित हुए। युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए न्याय के साथ-साथ सामाजिक न्याय के माध्यम से सम्मान पर ध्यान, जिसे उदाहरण के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में उजागर किया गया था, आवश्यक रूप से आर्थिक नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। वास्तव में जो आवश्यक है वह मूलभूत परिवर्तन से कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को देश या सर्वोच्च नेता से 'उपहार' के रूप में देखने के बजाय मानवाधिकारों, विशेष रूप से सामाजिक और आॢथक अधिकारों के ढांचे पर वापस जाना है। इसके लिए तत्काल दो बातों की आवश्यकता है। पहला काम श्रमिकों के अधिकार का विस्तार करके (बेहतर वित्त पोषित और अधिक सुलभ मनरेगा के साथ-साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत के माध्यम से) सभी के लिए बुनियादी सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करना है। भोजन का अधिकार, जो अभी भी अपर्याप्त है और कम से कम 100 मिलियन भारतीयों को इससे वंचित किया गया है। दूसरा है लाखों युवाओं की निराश आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नौकरियां पैदा करना है। यह प्राथमिक आर्थिक लक्ष्य बनना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक रोजगार के विस्तार की आवश्यकता है। सबसे पहले, रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है और 'योजना' के तहत श्रमिकों सहित सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को नियमित करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की जरूरतें पिछले दशक की नीतिगत गलतियों से प्रभावित हुई हैं। मोदी के 'नए कल्याणवाद' के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन इसे अधिक सटीक रूप से 'कल्याणवाद के आसपास नई ब्रांडिंग' के रूप में वर्णित किया गया है।

भूपिंद्र सिंह

राज्य में कब बनेगा खेल प्राधिकरण

इसके लिए प्राधिकरण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिएं तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें। राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए वजीफे की बात हो'

हिमाचल प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार में पहले तो खेल नीति पर काफी चर्चा पर चर्चा होता रही, मगर फिर खेल मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश सरकार की खेल नीति को कागजों में नया स्वरूप मिल ही गया। इस नीति में स्तरीय ढांचे की बात तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को खिलाड़ी के अनुरूप करने की कोशिश की गई जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देकर खिलाड़ी प्रदेश व देश को पदक जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर उठाकर जन गण मन की धुन पूरे विश्व को सुना सकें। हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन हुक्मरानों ने खेल विभाग को कभी खेल प्राधिकरण, तो कभी खेल संस्थान बनाने की वकालत की है, मगर हिमाचल प्रदेश में खेलों की हकीकत सबके सामने है। नई खेल नीति में राज्य खेल संस्थान का भी जिक्र है। पिछली भाजपा सरकार नई खेल नीति तो बना गई, मगर उसे धरातल पर उतारने से पहले ही सत्ता से बेदखल हो गई। नई बनी कांग्रेस सरकार से हिमाचल के खेल प्रेमियों को काफी आशा है। पहले विक्रमादित्य सिंह और अब यादविंदर गोमा खेल मंत्री हैं। क्या कांग्रेस सरकार हिमाचल में खेल प्राधिकरण बनाकर खेलों का व्यापक स्तर पर कायाकल्प करेगी? हिमाचल प्रदेश में कई खेलों के लिए विश्व स्तरीय खेल ढांचा तो बनकर तैयार हो चुका है, मगर प्रशिक्षकों व अन्य सुविधाओं के अभाव में वहां पर उस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी खेल संस्कृति का अभाव साफ देखा जा सकता है। धूमल सरकार में बनी खेल नीति में हिमाचल के खिलाडियों को सरकारी नौकरी में तीन प्रतिशत आरक्षण बहुत बड़ी सौगात है।

अब दो दशक बाद विभिन्न पहलुओं के ऊपर नई खेल नीति में सुधार किया गया है, मगर देखते हैं इसका जब जमीनी हकीकत से सामना होगा, तो वास्तव में सरकारी तंत्र कितना सही कार्यनिष्पादित करवा पाता है। खेलों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इससे जब हजारों विद्यार्थी फिटनेस कार्यक्रम से गुजरेंगे तो उनमें कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। खेल नीति में हिमाचली खिलाडियों से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन के लिए राज्य में अधिक से अधिक खेल अकादमियां व शिक्षा संस्थानों में खेल विंग, स्थान की सुविधा व प्रतिभा को देखते हुए सरकारी व खेल संघों के माध्यम से खोलने को कहा गया है तथा भविष्य में विभिन्न बड़ी कंपनियों से सीआरएस के माध्यम से राज्य में खेल ढांचे को सुदृढ़ करने मंशा भी है। मनरेगा से भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले फील्ड की सुविधा जुटाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न खेलों का स्तर राज्य में खेल छात्रावासों के खुलने के बाद भी अभी तक सुधरा नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ जुनूनी प्रशिक्षकों के बल पर कभी-कभी अच्छे परिणाम दे पाया हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एक खेलों को छोडक़र अधिकांश बार पिछड़ा ही रहा है।

हिमाचल हो या देश का कोई अन्य राज्य, उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए केवल प्रशिक्षक ही मुख्य किरदार दिखाई देता है। यही कारण है कि भारत का खेल मंत्रालय व कई राज्य भी अपने यहां हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षण केन्द्र खोलने पर जोर दे रहे हैं तथा वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों को अनुबंधित कर रहे हैं। खेलो इंडिया, गुजरात व पंजाब के उच्च खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी अधिक से अधिक इस तरह के हाई परफॉर्मेंस केंद्र व अकादमियां खोलनी होंगी।

इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता प्रदर्शन करवाने वाले अनुभवी प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने की शर्तों पर पांच वर्षों के लिए अनुबंधित करना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की संतानों को भी हिमाचल प्रदेश में रह कर ही पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधा मिल सके। केन्द्र व केरल सरकार की तर्ज पर प्रशिक्षकों को भी खिलाड़ी की तरह नगद ईनामी राशि व अवार्ड का प्रावधान किया गया है। आप हर विद्यार्थी को फिटनेस के लिए खेल मैदान में ले जाएंगे, तो उनमें से जरूर कुछ अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे। प्रतिभा खोज के बाद पढ़ाई के साथ-साथ प्रशिक्षण के लिए अच्छी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिएं। इसके लिए प्राधिकरण के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों को वैज्ञानिक आधार पर लंबी अवधि के प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिएं तथा प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों व पूर्व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाडियों के लिए सेमिनार व कम अवधि के प्रशिक्षक बनने के कोर्सेज हों। साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व लगने वाले कोचिंग कैम्प भी अनिवार्य रूप से लगाए जाएं, ताकि पहाड़ के लोगों को भी वही सुविधा उपलब्ध हो, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जा सकें।

राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए वजीफे की बात हो। जो खेल छात्रावास के बाहर हों, उन्हें भी खेल छात्रावास के अंतर्गत दैनिक खुराक भत्ता व अन्य सुविधाओं के ऊपर खर्च होने वाली राशि के बराबर वजीफा देने की वकालत हो। जिन अवार्डी खिलाडियों व प्रशिक्षकों के पास कोई नौकरी नहीं है, उन्हें साठ साल आयु के बाद पेंशन का प्रावधान हो। भारतीय खेल प्राधिकरण उपरोक्त ऐसी सभी योजनाओं को लागू करवाता है। हिमाचल प्रदेश में खेल प्राधिकरण बनता है, तो वह निःसंदेह हिमाचल प्रदेश की खेलों को ऊपर उठाने में अवश्य ही सहायक सिद्ध होगा।

पूरन सरमा

अपनी जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ें राजनीतिक दल

लोकसभा चुनाव के नतीजे उन लोगों के लिए एक झटके के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने समस्याग्रस्त एग्जिट पोल पर गलती से विश्वास कर लिया था, जो कि मोदी सरकार द्वारा इतनी मेहनत से तैयार की गई कहानी को जारी रखता है। कई राजनीतिक पंडितों ने उन झूठी...

लोकसभा चुनाव के नतीजे उन लोगों के लिए एक झटके के रूप में सामने आए हैं, जिन्होंने समस्याग्रस्त एग्जिट पोल पर गलती से विश्वास कर लिया था, जो कि मोदी सरकार द्वारा इतनी मेहनत से तैयार की गई कहानी को जारी रखता है। कई राजनीतिक पंडितों ने उन झूठी भविष्यवाणियों को साहसपूर्वक सही ठहराया है। हम वास्तविक परिणामों की व्याख्या करने के लिए पहले ही कूद पड़े। एक मुख्य व्याख्या यह है कि 'इंडिया' गठबंधन ने सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर जोर दिया और अधिक चतुर गठबंधन बनाए रखा। जाति के संदर्भ में उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट विकल्प भी गठबंधन ने बनाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक न्याय की आवश्यकता की मान्यता और साथ ही संविधान के अस्तित्व के बारे में आशंकाएं महत्वपूर्ण कारक थीं। साहसी राज्यों में स्थानीय कारकों ने भी भूमिका निभाई होगी।

अगली सरकार बनने पर उसे मतदाताओं के स्पष्ट संदेश को पहचानना होगा। आर्थिक मुद्दों का महत्व, बेरोजगारी और लगातार कम मजदूरी, स्व-रोजगार से अपर्याप्त आजीविका और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के प्रमुख संकटों को चुनावों के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। ये मुद्दे देश के अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां 'इंडिया' गठबंधन, खासकर कांग्रेस द्वारा किए गए वायदे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के कुछ हिस्सों में। विपक्षी पार्टियों ने सामाजिक न्याय के साथ-साथ आजीविका और रोजगार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके वायदे निःसंदेह अधिकांश मतदाताओं के बीच प्रतिध्वनित हुए। युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए न्याय के साथ-साथ सामाजिक न्याय के माध्यम से सम्मान पर ध्यान, जिसे उदाहरण के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र में उजागर किया गया था, आवश्यक रूप से आर्थिक नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। वास्तव में जो आवश्यक है वह मूलभूत परिवर्तन से कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को देश या सर्वोच्च नेता से 'उपहार' के रूप में देखने के बजाय मानवाधिकारों, विशेष रूप से सामाजिक और आॢथक अधिकारों के ढांचे पर वापस जाना है। इसके लिए तत्काल दो बातों की आवश्यकता है। पहला काम श्रमिकों के अधिकार का विस्तार करके (बेहतर वित्त पोषित और अधिक सुलभ मनरेगा के साथ-साथ शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरूआत के माध्यम से) सभी के लिए बुनियादी सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करना है। भोजन का अधिकार, जो अभी भी अपर्याप्त है और कम से कम 100 मिलियन भारतीयों को इससे वंचित किया गया है। दूसरा है लाखों युवाओं की निराश आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नौकरियां पैदा करना है।

बीएसई ने नकारी 4 जून को तकनीकी खराबी वाली बात, जानिए निवेशकों को दिए जवाब में क्या कहा

परिवहन विशेष न्यूज

BSE ने 4 जून को तकनीकी खराबी वाली बात को नकारा है। कई निवेशकों ने अपनी पोजीशन को बराबर करने में विफल रहने के लिए सोशल मीडिया पर शिकायत की थी। कई निवेशकों ने कट-ऑफ समय से पहले अपने म्यूचुअल फंड खरीदे हालांकि उन्हें नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) आवंटित किया गया था जो 4 जून के बजाय 5 जून के लिए फंड का मूल्य निर्धारित करता है।

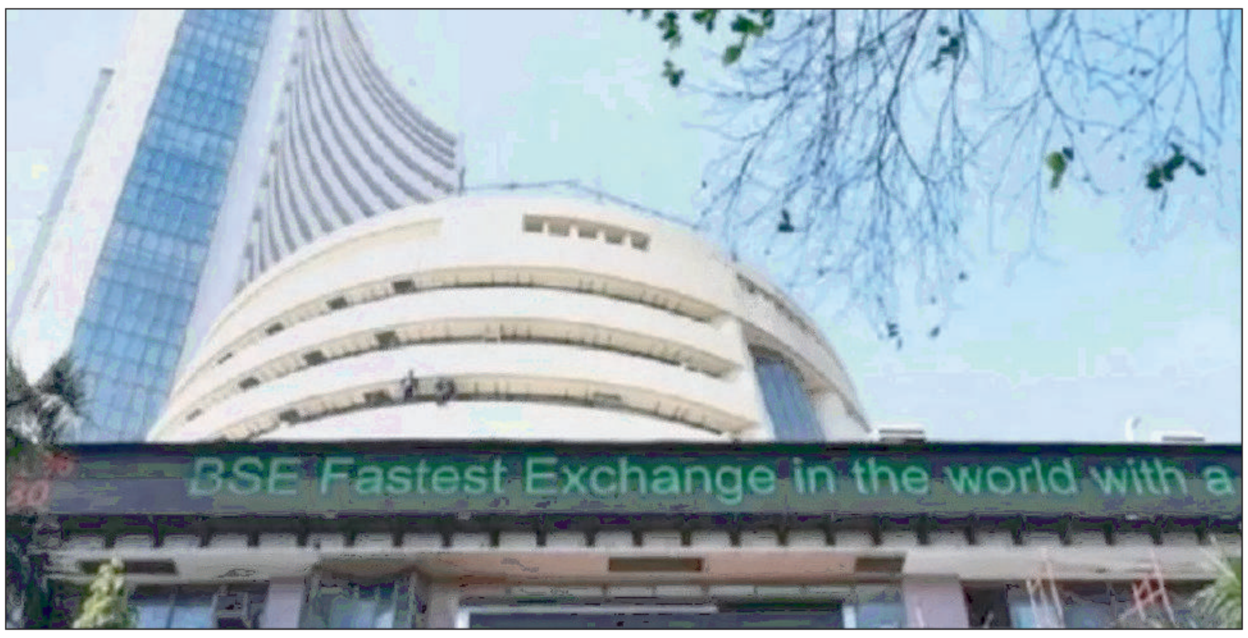

नई दिल्ली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों से भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण 4 जून को म्यूचुअल फंड खरीदने वाले निवेशकों को एनएवी आवंटित करने में देरी हुई और इसकी ओर से कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी।

निवेशकों ने की शिकायत

कई निवेशकों ने अपनी पोजीशन को बराबर करने में विफल रहने के लिए सोशल मीडिया पर शिकायत की थी। कई निवेशकों ने कट-ऑफ समय से पहले अपने म्यूचुअल फंड खरीदे, हालांकि उन्हें नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) आवंटित किया गया था, जो 4 जून के बजाय 5 जून के लिए फंड का मूल्य निर्धारित करता है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे निवेशकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। बीएसई ने एक बयान में कहा-

इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि 4 जून को बीएसई क्लियरिंग हाउस (आईसीसीएल) में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। प्रथम दृष्टया, कुछ ग्राहकों के लिए भुगतान एग्रीगेटर/बैंक से क्रेडिट/भुगतान का विवरण प्राप्त करने में देरी हुई, जिसके कारण एनएवी में देरी हुई।

4 जून को हुआ बड़ा फेरबदल

यह स्पष्टीकरण तब आया जब कई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ने 4 जून को बीएसई पर एक्सचेंज के म्यूचुअल फंड सिस्टम में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसके कारण अगले दिन (5 जून) ऑर्डर जारी हो गए, जब इक्विटी बाजारों ने अपने नुकसान की कुछ भरपाई कर ली थी।

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जिसमें निवेशकों की 31 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति डूब गई। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की शानदार जीत के एग्जिट पोल के अनुमान के बाद, बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार (3 जून) को 2,507 अंक या 3.4 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,469 के नए समापन शिखर पर बंद हुआ।

हालांकि, एक दिन बाद मंगलवार (4 जून) को शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें सेंसेक्स 4,390 अंक या 6 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,079 पर बंद हुआ। यह चार साल में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। बुधवार (5 जून) को सेंसेक्स ने अपने नुकसान की कुछ भरपाई की और सूचकांक 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया।

RBI के दिए झटके से उबर गया Paytm? सर्किट लिमिट में बड़ा बदलाव, रॉकेट बना स्टॉक

Paytm Share फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) के शेयरों में बीते कुछ महीने से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक कभी फ्रेश लोअर सर्किट को टच करता है तो कभी शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगता है। आज पेटीएम के अपर सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। पेटीएम का अपर सर्किट लिमिट 10 फीसदी हो गया है।

नई दिल्ली। फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) के शेयरों में बीते कुछ महीने से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक कभी फ्रेश लोअर सर्किट को टच करता है तो कभी शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगता है। पेटीएम के अपर सर्किट लिमिट को लेकर अपडेट आया। पेटीएम के अपर सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ। आपको बता दें कि आज से पेटीएम का अपर सर्किट लिमिट 10 फीसदी हो गया है।

पेटीएम के शेयर की परफॉर्मेंस

पिछले 1 महीने में पेटीएम के शेयर 14 फीसदी चढ़ें है। आज पेटीएम के शेयर 10 फीसदी चढ़कर 381.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ। आज सुबह कंपनी के स्टॉक 349 रुपये प्रति शेयर पर खुला था। शेयर में आई तेजी के बाद पेटीएम का अपर सर्किट 381.30 रुपये पर लॉक हो गया।

स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर सर्किट लिमिट को अपडेट करती है। अब एक्सचेंज ने पेटीएम के अपर सर्किट लिमट को 5 फीसदी से बदलकर 10 फीसदी कर दिया। जब भी शेयरों में भारी गिरावट आता है तो शेयरधारकों को ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिट तय कर देती है। इसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज सर्किट ब्रेकर लगा देता है।

पेटीएम पर आरबीआई का एक्शन

इस साल की शुरुआत पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर एक्शन लिया था। इस एक्शन के बाद पेटीएम के स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। जनवरी में जहां पेटीएम के शेयर की कीमत 700 रुपये से ज्यादा थी। वो आरबीआई के एक्शन के बाद 300 रुपये के करीब पहुंच गई।

क्या होता है सर्किट ब्रेकर

जब भी शेयर मार्केट या फिर किसी एक कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आती है तो उस गिरावट से निवेशकों को ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाता है। 2 जुलाई 2001 को स्टॉक एक्सचेंज ने इंडेक्स-बेस्ड मार्केट-वाइड सर्किट ब्रेकर लगाया था। यह ब्रेकर स्टॉक मूवमेंट को कंट्रोल करता है।

10 फीसदी, 15 फीसदी और 20 फीसदी के उतार-चढ़ाव आने पर सर्किट ब्रेकर लगता है। यब सर्किट ब्रेकर तब लगता है जब कोई शेयर इस सीमा तो पार कर देता है।

विदेश जाना हुआ आसान, इस इंटरनेशनल रूट पर एयर इंडिया ने शुरू की नॉन-स्टॉप फ्लाइट

एयर इंडिया ने अगस्त से बेंगलुरु और लंदन गैटविक (Gatwick) के बीच नॉन-स्टॉप सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइन से इससे संबंधित प्रेस रिलीज जारी की थी। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह इस साल 18 अगस्त से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और लंदन गैटविक (एलजीडब्ल्यू) के बीच नॉन-स्टॉप सेवाएं शुरू करेगी।

नईदिल्ली। एयर इंडिया ने अगस्त से बेंगलुरु और लंदन गैटविक (Gatwick) के बीच नॉन-स्टॉप सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइन से इससे संबंधित प्रेस रिलीज जारी की थी। बेंगलुरु ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे से जुड़ने वाला पांचवां भारतीय शहर बनने के साथ, एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह इस साल 18 अगस्त से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और लंदन गैटविक (एलजीडब्ल्यू) के बीच नॉन-स्टॉप सेवाएं शुरू करेगी। यह सेवा यूके में एयर इंडिया की उपस्थिति को और मजबूत करेगी। इससे भारत और यूके के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे।

एयर इंडिया ने आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा कि एयर इंडिया बेंगलुरु और लंदन गैटविक के बीच साप्ताहिक 5 गुना संचालन करेगी। इस प्रकार लंदन गैटविक से इसकी उड़ानों की कुल संख्या 17 गुना हो जाएगी। इस मार्ग पर एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का उपयोग करेगी। इसमें बिजनेस क्लास में 18 फ्लैट बेड और इकोनॉमी में 238 विशाल सीटें होंगी।

प्रेस रिलीज के अनुसार, एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने कहा हम अपने मेहमानों को बेंगलुरु और लंदन गैटविक के बीच सुविधाजनक, नॉन-स्टॉप उड़ानें प्रदान करके खुश हैं। यह नया मार्ग इन दो महत्वपूर्ण व्यावसायिक और अवकाश स्थलों के बीच यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करता है, और हमारे वैश्विक नेटवर्क के विस्तार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

इंफ्रा सेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी नई सरकार : ICRA

ICRA ने कहा कि नई सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी जिसमें रेलवे सड़क और पानी पर अधिक व्यय होगा। सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए नई सरकार की प्राथमिकता में कुछ बदलाव हो सकता है। मूडीज एनालिटिक्स ने भी कहा कि गठबंधन सरकार में कम होती राजनीतिक स्थिरता और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

नईदिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने शुक्रवार को कहा कि नई सरकार रेल, सड़क और पानी पर ज्यादा आवंटन के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेगी। नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। हालांकि, उम्मीद से कम सीटें मिलने के कारण उनकी पार्टी भाजपा को गठबंधन सरकार में सत्ता साझा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए नई सरकार की प्राथमिकता में कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन विकास की गति बनाए रखने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत व्यय को जारी रखे जाने की उम्मीद है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से जीडीपी पर सकारात्मक असर होता है और इससे रोजगार का सृजन भी होता है। चुनावों में राजग को कुल 293 सीटें मिली हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से ज्यादा है।

गठबंधन से निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी धीमी

मूडीज एनालिटिक्स ने शुक्रवार को कहा कि गठबंधन सरकार में कम होती राजनीतिक स्थिरता और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। मूडीज एनालिटिक्स ने एक नोट में कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का मतलब है कि संसद में गतिशीलता बदलने वाली है।

इससे गठबंधन के सहयोगी नीतिगत निर्णयों में प्रभाव और लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे शासन के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की अनुमति मिलेगी। मूडीज एनालिटिक्स की एसोसिएट इकोनमिस्ट अदिति रमन ने कहा कि कम होती राजनीतिक स्थिरता और आम सहमति बनाने की आवश्यकता निकट भविष्य में निवेशकों के विश्वास को कम कर सकती है।

शेयर मार्केट के साथ भारतीय करेंसी ने भी लगाई दौड़, डॉलर के मुकाबले इतने पैसे चढ़कर बंद हुआ रुपया

शेयर बाजार ऑल-टाइम हाई पर बंद हुआ। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे चढ़कर बंद हुआ। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय करेंसी 83 .46 पर मजबूत खुली और ग्रीनबैक के मुकाबले 83 .48 से 83 .37 के दायरे में चली गई। अंतत: डॉलर के मुकाबले 83 .39 (अनंतिम) पर बंद हुई। आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है।

नई दिल्ली। इस हफ्ते बाजार में आई भारी गिरावट को रिकवर करने में शेयर मार्केट को 3 दिन का समय लगा। हालांकि, भारतीय करेंसी अभी भी रिकवरी मोड में ही है। आज शेयर बाजार ऑल-टाइम हाई पर बंद हुआ। बाजार में आई तेजी के साथ रुपये में भी तेजी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे चढ़कर बंद हुआ।

लगातार 8वीं बार रेपो रेट (Repo Rate) को स्थिर रखा गया। आज एमपीसी बैठक (RBI MPC Meet 2024) में लिए गए फैसलों का एलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि एमपीसी बैठक के सदस्य ने इस बार भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया।

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि विदेशों में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर अमेरिकी मुद्रा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कम कीमतों ने भी स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया। हालांकि, विदेशी फंड के बहिर्वाह ने रुपये में तेजी को रोक दिया।

डॉलर और रुपये के बीच कारोबार

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय करेंसी 83.46 पर मजबूत खुली और ग्रीनबैक के मुकाबले 83.48 से 83.37 के दायरे में चली गई। अंततः डॉलर के मुकाबले 83.39 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 14 पैसे की बढ़त दर्ज करती है।

पिछले सत्र यानी गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटकर 83.53 पर बंद हुआ।

एमपीसी बैठक में लिए गए फैसले

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को लगातार आठवीं बार नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह मुद्रास्फीति पर कड़ी निगरानी बनाए रखेगा। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।

डॉलर इंडेक्स का क्या है हाल?

दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.03पर बना हुआ है। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 0.25 प्रतिशत गिरकर 79.67 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर है।

रिकॉर्ड हाई पर बाजार

आज बीएसई सेंसेक्स 1,618.85 अंक या 2.16 प्रतिशत बढ़कर 76,693.36 अंक पर बंद हुआ। यह अभी तक ऑल-टाइ हाई है। एनएसई निफ्टी भी 468.75 अंक या 2.05 प्रतिशत बढ़कर 23,290.15 अंक के अपने नए शिखर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशक गुरुवार को भारतीय इक्विटी

आरबीआई के भीतर बढ़ रही ब्याज दरों में कटौती की आवाज, अब मुश्किल होगा रेट कट को टालना?

रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के चार सदस्यों ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने के पक्ष में वोट दिया। वहीं दो सदस्यों- आशिमा और जयंत का मत इसके विपरात था। उनका मानना था कि अब करीब डेढ़ बाद ब्याज में कटौती करने की जरूरत है। 6 सदस्यों वाली आरबीआई की कमेटी रेट कट पर बहुमत के आधार पर फैसला लेती है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) के रेट-सेटिंग पैनल के भीतर नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के सुर उठ रहे हैं। इस पैनल के मेंबर जयंत आर वर्मा लंबे वक्त से ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती की वकालत कर रहे हैं। अब उन्हें एक एक्सटर्नल मेंबर आशिमा गोयल का भी साथ मिल गया है। आज रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के चार सदस्यों ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने के पक्ष में वोट दिया। वहीं, दो सदस्यों- आशिमा और जयंत का मत इसके विपरात था। उनका मानना था कि अब करीब डेढ़ बाद ब्याज में कटौती करने की जरूरत है। 6 सदस्यों वाली आरबीआई की कमेटी रेट कट पर बहुमत के आधार पर फैसला लेती है। केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति बयान के मुताबिक, 'डॉक्टर शशांक भिडे, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल देबब्रत पात्रा और श्री शशिकांत दास ने पॉलिसी रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर जस का तस रखने के पक्ष में वोट दिया।

रिजर्व बैंक ने विदेश से गोल्ड वापस मंगाया, क्या अब सस्ता होगा सोना? RBI गवर्नर ने दिया जवाब

सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसकी कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं। साथ ही प्राचीन समय से इसे यूनिवर्सल करेंसी का दर्जा मिला है। यह किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। अब अगर आरबीआई देश में सारा सोना जमा रखता है तो किसी राजनीतिक उथलपुथल या कुदरती आफत के समय यह उसके हाथ से जा भी सकता है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से गोल्ड रिजर्व को युद्ध स्तर पर बढ़ा रहा है। इसका मकसद डॉलर पर निर्भरता घटाने के साथ मुद्रास्फीति से मुकाबले की तैयारी करना भी है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने पिछले दिनों ब्रिटेन के बैंक जमा अपने सोने को भी वापस देश में मंगाया था। इससे कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि गोल्ड रिजर्व बढ़ने और विदेश से अपना सोना वापस मंगाने से क्या देश में गोल्ड सस्ता हो सकता है। अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद स्थिति साफ की है।

उन्होंने कहा, 'रिजर्व बैंक ब्रिटेन से 100 मीट्रिक टन सिर्फ इसलिए वापस लाया है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए।' आरबीआई गवर्नर के इस बयान से साफ है कि सोने के दाम नहीं घटने वाले।

गोल्ड रिजर्व बढ़ाने से सोना सस्ता क्यों नहीं होता?

अब मान लीजिए कि आपके पिताजी सोना खरीदकर लाते हैं और उसे तिजोरी में रख देते हैं। उनका इरादा है कि जब अचानक कोई मुसीबत आएगी, तो इस सोने का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप या किसी और घरवाले को उस सोने से कोई तात्कालिक फायदा नहीं होने वाला।

यही चीज आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के साथ भी है। दुनियाभर में जिस तरह से भूराजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और उससे महंगाई का खतरा भी अधिक हो गया है। इसी से बचने के लिए आरबीआई गोल्ड रिजर्व अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। यह एक तरह से किसी बड़े आर्थिक खतरे से निपटने की तैयारी है।

अगर आरबीआई विदेश से सस्ते में सोना खरीदकर लाता और उसे बाजार में बेचता या लोगों को बांटता, तो उससे सोने की कीमतें कम होने की संभावना रहती। लेकिन, न तो यह व्यावहारिक चीज है और न ही आरबीआई का ऐसा कोई इरादा है। इसका मतलब कि गोल्ड रिजर्व बढ़ने या विदेश से सोना वापस लाने से सोने की मार्केट प्राइस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला।

विदेश में सोना क्यों जमा करता है आरबीआई?

सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि इसकी कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं। साथ ही, प्राचीन समय से इसे यूनिवर्सल करेंसी का दर्जा मिला है। यह किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। अब अगर आरबीआई देश में सारा सोना जमा रखता है, तो किसी राजनीतिक उथलपुथल या कुदरती आफत के समय यह उसके हाथ से जा भी सकता है।

यही वजह है कि दुनियाभर के ज्यादातर देश अपने गोल्ड रिजर्व को अलग-अलग देशों में जमा करते हैं। जैसे कि निवेशक जोखिम कम करने के लिए अपनी दौलत को अलग-अलग चीजों में निवेश करते हैं। साथ ही, गोल्ड रिजर्व को दूसरे में जमा करने से उनके साथ व्यापार करने में भी सहूलियत होती है। कई बार विदेश में सोने पर ज्यादा ब्याज भी मिलता है।

सोने को इतनी अहमियत क्यों दे रहे केंद्रीय बैंक?

सोना फिलहाल डॉलर के विकल्प के तौर पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। महंगाई के खिलाफ सबसे कारगर हथियार तो यह हमेशा से रहा है। सोने की अहमियत का अंदाजा आप रूस की हालत से लगा सकते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों ने अपने देश में मौजूद रूस के 300 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त कर लिया यानी रूस के पास जो यूरो और डॉलर थे, उनकी वैल्यू जीरो हो गई।

अब अगर रूस डॉलर या यूरो के बजाय सोने का भंडार बनाता, तो इसका दाम भले ही एकसाथ 20 फीसदी गिर जाता, लेकिन यह उसे शून्य से बेहतर होता, जो उसके पश्चिम में मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार का हाल हुआ।

भारतीय जनता का ऐसा फैसला जिसे भारतीय राजनीति में लंबे समय तक याद रखा जाएगा

परिवहन विशेष न्यूज

1. भाजपा और उसके सहयोगियों को ऐसी जीत दी है जो हार जैसी लगती है.

2. कांग्रेस गठबंधन को ऐसी हार दी है जो जीत जैसी लगती है.

3. सब राजनीतिक दल मिल गए उसके बावजूद बीजेपी की 50-60 सीट घटा पाए.

लेकिन संदेश यह दे रहे है कि देश ने मोदी को नकार दिया है

ओडिशा में ऐतिहासिक जीत है, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में सरकार बन रही है, एमपी - दिल्ली - गुजरात में क्लीन स्वीप है, दक्षिण और ओडिशा में सीटें जबरदस्त बढ़ी हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी, लेकिन मोदी को हरा दिया. मोदी को कमजोर कर दिया. खुद की सरकारबने या ना बने पर मोदी को कमजोर कर दिया है.

इसी में खुश हैं.

कमजोर कोई हुआ है तो वो है देश.. भारत इकलौता ऐसा देश होगा जो 8% की विकास दर से बढ़ने के बावजूद आज टाइम मशीन में बैठकर 90 के दशक में वापस चला गया है.**जहां इससे पूछो, उससे समझो (समझौते वाली) सरकारें चला करती थीं, शायद देश की जनता को वही यही मंजूर है.**

दस साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई किंतु दस साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा 241 सीटों पर बैठी है.**यही अंतर है..!** 98 सीट वाले कह रहे हैं कि 241 सीट वाले को जनता ने नकार दिया है. **इससे दिलचस्प नतीजे और क्या होंगे..** केरल में खाता खुला और मध्यप्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार लाखो मतों पराजित हुए हैं.

देश का पहला ऐसा चुनाव है.. जिसमें, जो पार्टी जीती उससे ज्यादा खुशी हारने वाली पार्टी मना रही है. जितनी सीटे अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जीती है उतनी सीटे सारे इंडि गठबंधन वालों ने मिलकर भी नहीं जीती है.

आज ठाकुर भी खुश है..
जाट भी खुश है..
आज यादव भी खुश है..
आज दलित भी खुश है..
आज मुस्लिम भी खुश है..
बस आज देशभक्त निराश है..!

10 सालों तक मुसलमान को कांग्रेस से कुछ नहीं मिला पर इन्होंने कॉंग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, वही 10 सालों तक सब कुछ दिया..**ग़ज़ब**

कुछ तो बात जरूर है हम हिन्दूओ में, यूं ही कोई बरसों तक गुलाम नहीं होता। बर्बाद ए हिंद के लिए एक ही जयचंद काफी था। हाल ए हिंद क्या होगा जब हर गांव हर शहर में जयचंद है.

हिंदू से अच्छे मुसलमान रहे जिन्होंने यूपी और बंगाल मैं बता दिया की हम एक है और हिंदुओं ने अयोध्या मे बीजेपी को हराकर कर बता दिया, कि हम क्या है.

इस लोकसभा चुनावों के रिजल्ट देखकर, अब हमे इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत नही है क्योकी हम जान गए है, कि हमारे पुरखे क्यो और कैसे गुलाम बने थे.!!

इसी को ध्यान में रखकर शायद, वीर सावरकर जी ने सच कहा था कि मुझे अंग्रेजों का और मुस्लिमों का भय नहीं है मुझे तो भय है उन जातिवादी सेक्युलर हिन्दूओं का जो हिन्दू होकर भी हिंदूओं का विरोध करते हैं..!!*

सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की..

भारत मे सबसे ज्यादा मत लगभग 38% भाजपा को मिले..

सबसे ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी जीते, जो रिकार्ड है..

अनेक प्रदेशों मे विपक्ष का सफाया.

10 साल की सरकार के बाद भी सबसे बडी पार्टी फिर लगभग 23% मत पाने वाले ऐसा क्यों कह रहे है की इनको नकार दिया। भारत की जनता मतदान में 60%, एग्जिट पोल में 99% और मतगणना में रुचि 101% की रखते हैं।

आज EVM सती सावित्री घोषित हुई.

हिन्दू ऐसी गाय हैं जो पालने वाले किसान से नाराज होकर स्वयं कसाई के पास चले जाते हैं.

अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद मिला जनादेश बता रहा है की हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता मथुरा मे श्रीकृष्ण और काशी मे शिवलिंग मस्जिद मे रहे या मंदिर मे!!

आईपीएस अन्ना मलाई चुनाव हार गया और जेल में बंद आतंकवादी अमृतपाल 1लाख+ से जीत गया.**कल्पना कीजिए क्या सोच है.**

रामायण का अंतिम ज्ञान. राजा राम ने कष्ट सहकर प्रजा को सुखी संतुष्ट करने का अथक परिश्रम से प्रयास किया, किंतु प्रजा संतुष्ट नहीं हुई, **क्या वही स्थिति आज नहीं है ?**

भारत माता की जय

9 जून शाम सवा 7 बजे, तारीख नोट कर लें! राष्ट्रपति भवन में मोदी लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ

परिवहन विशेष न्यूज

मोदी सरकार 3.0 के गठन की कवायद शुरू हो गई है। आज एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को नई सरकार के गठन का न्योता दिया। अब 9 जून को शाम सवा 7 बजे राष्ट्रपति भवन में मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे।

नई दिल्ली: मोदी सरकार 3.0 के गठन का रास्ता साफ हो चुका है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम सवा 7 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन का न्योता दिया। राष्ट्रपति ने मोदी को दही-चीनी खिलाकर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। पीएम मोदी शुक्रवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचे। इससे पहले एनडीए के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना समर्थन पत्र सौंपा और नई सरकार बनाने की पेशकश की।

पीएम ने 9 जून को शपथ लेने की बात कही

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को बताया है कि शपथ ग्रहण के लिए 9 जून की शाम को उन्हें सुविधा रहेगी, तब तक वह मंत्री परिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि 18वीं लोकसभा में पांच वर्ष के कार्यकाल में वे उसी गति और समर्पण भाव से देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

एनडीए की बैठक में मोदी चुने गए संसदीय दल के नेता

उन्होंने कहा कि आज सुबह एनडीए की बैठक हुई और सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है। एनडीए के सभी साथियों ने राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री मनोनीत के रूप में नियुक्ति दी है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।

राष्ट्रपति भवन में चल रही तैयारियां

4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें अपना नेता चुना और समर्थन पत्र दिए हैं। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन को 5 से 9 जून तक आमजनों के लिए बंद रखा गया है।

फर्जी आधार से संसद भवन में घुसने वाले थे, CISF ने तीन मजदूरों को ऐसे पकड़ा

दिल्ली के संसद भवन के अंदर फर्जी आईडी कार्ड की मदद से घुसने की कोशिश कर रहे तीन मजदूरों को पकड़ लिया गया। तीनों को वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने धर दबोचा। पुलिस मजदूरों के ठेकेदारों से भी पूछताछ कर रही है।

नई दिल्ली: संसद भवन परिसर में तीन मजदूरों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर घुसने की नाकाम कोशिश की। समय रहते संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने पकड़ लिया। संसद मार्ग पुलिस को तीनों को हवाले कर दिया। तीनों से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। पुलिस उनके ठेकेदार से भी पूछताछ कर रही है। सभी मजदूरों के आधार कार्डों की जांच की जा रही है। पुलिस तीनों से उनके मकसद के बारे में भी जानकारी ले रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 जून की रात 8 बजकर 56 मिनट पर सीआईएसएफ जवानों ने संसद भवन परिसर के फ्लैट गेट के पास चेकिंग के दौरान तीन मजदूरों कासिम, मोनिस और शोएब को वहां पर संदिग्ध हालत में देखकर पकड़ा। पूछताछ करने पर उनके आधार कार्ड देखे वह भी फर्जी थे। तीनों मजदूर यही जाली आधार कार्ड दिखाकर परिसर में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को मामले की जानकारी दी गई।

संसद भवन की सुरक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तीनों से पूछताछ की। पता चला कि तीनों डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा काम पर रखा गया था। वह आईजी 7 और में एमपी के लाउंज के निर्माण में लगे हुए थे। तीनों से पूछा गया कि फर्जी आधार कार्ड कहां से और कब बनवाया था। कंपनी के अधिकारियों और ठेकेदार से भी मामले में जवाब मांगा गया है। तीनों के मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं, यह भी पता किया जा रहा है। तीनों रात के वक्त क्यों अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों के बारे में अन्य मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। तीनों को फिलहाल संसद मार्ग पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल का विपरीत असर किडनी, व हार्ट पर हो सकता हैर: डॉ सूरज शूर

अमृतसर (साहिल बेरी) शूर हस्पताल खजाना गेट के डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉ सूरज शूर ने बताया कि दवाई और इंसुलिन की डोज के बाद भी अगर शुगर लेवल कंट्रोल में ना रहे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें, कई बार अनकंट्रोल लेवल पर शुगर होने के बाद भी लक्षण दिखाई नहीं देते, तो कई बार अचानक इसका असर होता है और यह असर बड़े लेवल पर होता है जो शरीर के कई अंगों को डैमेज भी कर देता है1 सबसे पहले अनकंट्रोल शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए और 200 के नीचे रखना चाहिए, कई बार शुगर लेवल 300 के ऊपर होने पर भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मरीज ठीक हैं, उन्हें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए तथा पूरा इलाज कराना चाहिए, अगर एक-दो दिन में शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता तो यह एक बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य स्थित है1 अनकंट्रोल शुगर लेवल का विपरीत प्रभाव जैसे के आंखों के रेटिना पर असर हो सकता है, किडनी पर असर होता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, नसों पर भी इसका असर होता है, हार्ट पर भी विपरीत असर होता है और शुगर लेवल कितना ज्यादा होता है इंफेक्शन बढ़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिस से पीड़ित लोगों के रक्त में शर्करा कि अचानक गिरावट बेहोशी या दौरे का कारण बन सकती है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति चलते चलते चक्कर खाकर गिर सकता है, उसे दौरा, स्ट्रोक, और कोमा में भी जाने का खतरा बना रहता है, इस बीमारी के इलाज में पीड़ित मरीज को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है1

हार फैजाबाद सीट से हुई तो दोष सिर्फ अयोध्या को क्यों..?

अयोध्या ने हरा दिया .....

सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक यही नैरेटिव बनाया जा रहा है'.ताकि देश की एकमात्र हिंदुओं के प्रति थोड़ा बहुत झुकाव रखने वाली BJP भी परे हो जाये'

UP से लेकर कुछेक राज्यो को छोड़कर पूरे भारत ने BJP की बैंड बजायी है 'फिर दोष सिर्फ अयोध्या को क्यों' ?

पहली बात अयोध्या नाम से कोई लोकसभा की सीट है ही नही 'वो फैजाबाद सीट है 'हार फैजाबाद सीट से हुई तो दोष सिर्फ अयोध्या को क्यों..?

अयोध्या नाम से विधानसभा की सीट है, और यहां से BJP ने 2500 वोटों से लीड ली है, यानी अयोध्या से जीत है..फिर दोष सिर्फ अयोध्या को क्यों' ?

आंखें खोलिए और भगवान राम के पवित्र जन्म स्थल को गरियाना बन्द कीजिये, वामपंथीयों के नैरेटिव का शिकार मत बनिये, इन्हें इन केन प्रकरेण हिंदुओं को नीचा दिखाना है उनकी एकता (थोड़ी बहुत) को तोड़ना है।

अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में पाँच विधानसभा क्षेत्र लगते हैं,,

१--अयोध्या(फैज़ाबाद और राममंदिर का क्षेत्र)

२--रुदौली(अयोध्या मंदिर से 40 किलोमीटर लगभग)

*--मिल्कीपुर(अयोध्या से लगभग 30 किलोमीटर)

४--बीकापुर(अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर)

५---दरियाबाद(अयोध्या से लगभग 55 किलोमीटर, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र)

अयोध्या में हम 4667 वोटों से जीते हैं क्योंकि हिन्दू वोट संगठित था और खुलकर वोट पड़े, वोटिंग लाइन जय जय श्रीराम का उदघोष करके वोट कर रही थी जबकि सपा को सबके वोट पड़े, बीकापुर जो कि अयोध्या मंदिर से 22 से 25 किलोमीटर दूर है, एक ग्रामीण क्षेत्र है और पिछड़ा भी क्योंकि इधर किसी ने ढंग से ध्यान ही नही दिया आज तक और सपा ने आरक्षण हटाने की अफवाह को ढंग से कैश किया। मिल्कीपुर से सपा के विजयी कैंडिडेट अवधेश प्रसाद विधायक हैं तो उनका गढ़ समझिए लेकिन फिर भी तगड़ी फाइट मिली उनको दरियाबाद जो है ही मुस्लिम क्षेत्र, सांसद जी बस प्रतिनिधि भेजते थे या चुनाव के समय फ़ोटो खिंचाने जाते हैं उधर हार की वजह यही है, बाकी राम के नाम पर वोट उधर भी पड़े, कुल मिला जुलाकर जो लोग गाली दे रहे अयोध्या वालों को उनको यही कहूँगा की पहले अयोध्या की भौगोलिक स्थिति को समझिये और रही बात मंदिर की, विकास की इन्फ्रा की, तो सुनिये अयोध्याजी में सिर्फ राममन्दिर ही बना है अभी तक वो

भी पूरा नही, सड़क बनी है तो सिर्फ 8 किलोमीटर जिसे रामपथ कहते हैं, नयाघाट (वीणा चौराहा) से रामघाट सिर्फ 2 किलोमीटर, उसके अगले बगल सूर्य पोल लग गया है, सजावट के लिए बस, बाकी अयोध्या की गलियाँ पैदल चलने लायक तक नही हैं,

अयोध्या से नही हारे हैं हिन्दू, बहुत से लोग कह रहे कि अयोध्या जाओ तो घर से प्रसाद बनाकर ले जाओ वो जान लें अयोध्या जी मे देशी घी के बेसन के लड्डू को जियो टैग मिल चुका है और इसका एक स्पेशल मॉडल का डिब्बा भी है, हनुमानगढ़ी में वही प्रसाद के रूप में अर्पित होता है, बाकी और कुछ भी नही चढ़ा सकते उधर कनक भवन में खुरचन पेड़ा चढ़ता है, लोग अपने ही उन हिन्दू भाइयों का बायकॉट करने के लिए कह रहे हैं जो जीवनपर्यंत मंदिर के लिए लड़ने और बाहरी कार सेवकों के लिए कार सेवकपुरम बनाये,, खाना पानी की व्यवस्था किये, मित्रवत प्रेम दिए। जिनका बायकॉट करना है उनका नही करेंगे, अपने ही भाइयों का करेंगे । मुझे तो लग रहा कहीं यह किसी की कोई चाल तो नही पूरे देश को राममन्दिर मुहिम से अलग करने की।

अयोध्यावासियों के लिए पुनः विचार करें

नई सरकार कैसा होगा वर्किंग स्टाइल, राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम ने बता दी पूरी बात

परिवहन विशेष न्यूज

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने एनडीए संसदीय दल के नेता को सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद अब नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति से मिलने के बाद मोदी ने नई सरकार की प्राथमिकताएं बताई।

नई दिल्ली : एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगली एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने के तुरंत बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को लेकर अपनी बात रखी। मोदी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून की शाम को होगा। राष्ट्रपति भवन के सामने बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने मुझे अभी फोन किया और मुझे पीएम के रूप में काम करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे शपथ समारोह के बारे में सूचित किया है।

हर क्षेत्र में दिखेगा बदलाव

मोदी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति जी से कहा है कि 9 जून की शाम को हम सहज हो जाएंगे। अब राष्ट्रपति भवन बाकी विवरण तैयार करेगा और तब तक हम मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सौंप देंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी ने यह उल्लेख करते हुए कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद यह पहला चुनाव था। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार, एनडीए सरकार को लोगों ने देश की सेवा करने का मौका दिया है ... मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि पिछले दो कार्यकालों में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है और 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ षड्यंत्र के लिए देश विपक्ष को माफ नहीं करेगा, पीएम मोदी ने क्यों कही ये बात

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैंने चुनाव के समय पहली बार देखा है, शायद हर तीसरे दिन चुनाव आयोग के काम में रुकावट आए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। इस काम में एक ही टोली थी। सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में वो चुनाव के पीक आवर्स में यानी कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उस इंस्टीट्यूट पर लगा दो, ताकि चुनाव का कोई भी परिणाम आए ताकि हम भारत को भी दुनिया के सामने बदनाम कर लें। इस षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन, देश इन लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा।

उन्होंने आगे जिक्र किया कि मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और ये दुनिया में जाकर बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, मोदी आकर बैठ गए हैं, एक चाय वाला यहां पर कैसे पहुंच गया। कुछ तो गड़बड़ की होगी। इनका चुनाव प्रक्रिया के प्रति भारत के लोगों पर अविश्वास पैदा करने का षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता और गहनता सबको जानने और समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे में इस बार के चुनाव के नतीजे देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद दो दिनों तक कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि हम लोग हार गए। लेकिन, देशवासी जानते हैं कि हम ना तो हारे थे, ना ही हारे हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय से उन्माद पैदा नहीं होता और हम पराजय का उपहास भी नहीं करते हैं।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले ईवीएम का विरोध करते हैं, मैं इसे सिर्फ चुनाव के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी की सोच वाले लोग हैं। वह टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं देते हैं और न इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईवीएम में ही नहीं दिखाई दिया है, यूपीआई में दिखा। हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया। ये मानने को तैयार नहीं हैं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। कई देश कहते हैं कि हमें भी आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को लेकर बार-बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर परेशानी पैदा की। विपक्षी गठबंधन के लोग प्रगति, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं।

अगले 5 साल बहुत उपयोगी होंगे

उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के इस कार्यकाल में भारत विश्व के लिए विश्वबंधु बनकर उभरा है। इसका अधिकतम लाभ अब मिलना शुरू हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। विश्व अनेक संकटों, अनेक तनावों, आपदाओं से गुजर रहा है... हम भारतीय भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। विकास के लिए दुनिया में हमारी प्रशंसा भी हो रही है।

मान,सम्मान और संस्कार इसे ही कहते हैं...जब 'शिखर' के सामने झुक गए पीएम मोदी, तस्वीरें देख लीजिए

पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने पहुंचे।

पीएम मोदी ने आडवाणी को देखतेही दूर से जोड़ लिए हाथ।

पीएम मोदी बीजेपी के शिखर पुरुष रहे आडवाणी के सामने सम्मान में झुक गए।

पीएम मोदी ने आडवाणी का जब हाथ अपने हाथ में लिया तो पूर्व डिप्टी पीएम के चेहरे पर एक अलग ही भाव थे।

पीएम से मुलाकात के बाद आडवाणी काफी शांत मुद्रा में दिखे।

भारत रत्न से सम्मानित पार्टी के मार्गदर्शक से मिलने के बाद मोदी के चेहरे पर भी संतोष के भाव थे।

तीसरी बार मौका देने के लिए धन्यवाद

पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए को तीसरी बार सेवा देने के लिए लोगों को धन्यवाद देते हुए, पीएम मोदी ने सभी को आश्वासन दिया कि 18वीं लोकसभा में, ₹हम उसी गति और समर्पण के साथ देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा एक तरह से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा से भरी है... यह 18वीं लोकसभा उन सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जब देश 2047 में आजादी के 100 साल मना रहा होगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023